▸▸वर्ष : 34 ▸▸अंक : 309 ▸▸मुंबई, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 ▸▸RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸मूल्य : 3 रुपए ▸▸epaper.dobajedopahar.com ▸▸संपादक : अरुण लाल ▸▸संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

क्या आपने मतदान किया है?

लोकतंत्र में मतदान न करना,
भले ही **कानूनी अपराध न हो,**
लेकिन यह एक **नैतिक अपराध है।**

जाइए और मतदान कीजिए!

बड़ी संख्या में भागीदार बनें
अपनी **जिम्मेदारी** निभाइए

१५ जनवरी २०२६ | सुबह ७:३० बजे से शाम ५:३० बजे तक

Published in public interest by SWARNIM YUG FOUNDATION.

महापालिका संग्राम

DBD दो बजे दोपहर II

मुंबई, गुरुवार, 15 जनवरी 2026

ठाणे मनपा चुनाव

2013 केंद्रों पर आज पड़ेगा वोट

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी) के आम चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज होने वाले मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। ठाणे मनपा क्षेत्र के 11 डिवीजनों में कुल 2013 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा और मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी, पोलिंग ऑफिसर (1, 2 और 3) और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मनपा आयुक्त और चुनाव अधिकारी सौरभ राव ने पुष्टि की है कि सभी केंद्रों पर ईवीएम और स्टेशनरी सहित आवश्यक चुनावी सामग्री का वितरण संपन्न हो चुका है।

- प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद
- सामग्री वितरण संपन्न, कर्मचारी केंद्रों पर तैनात

टीएमटी की 275 बसों से पहुंची पोलिंग पार्टियां

चुनावी लॉजिस्टिक्स को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक परिवहन व्यवस्था की थी। सामग्री वितरण केंद्रों से मतदान केंद्रों तक कर्मचारियों और सामान को पहुंचाने के लिए ठाणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट (टीएमटी) की 275 बसों का बेड़ा तैनात किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, आज दोपहर तक सभी पोलिंग पार्टियां अपने निर्धारित स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गईं। वहां पहुंचकर कर्मचारियों ने बूथ लेआउट और अन्य तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सामग्री वितरण के लिए शहर भर में अलग-अलग केंद्र बनाए गए थे, जिनमें न्यू होराइजन स्कूल (माजीवाड़ा), बेथनी अस्पताल के पास (वर्तकनगर), और मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम (मुंब्रा-दिवा) प्रमुख शामिल हैं।

प्रमुख सखी और आदर्श केंद्र

- हीरानंदानी एस्टेट : सखी बूथ (पोतदार स्कूल) और आदर्श केंद्र (हीरानंदानी फाउंडेशन)।
- नौपाड़ा-कोपरी : सखी और आदर्श केंद्र डॉ. बेडेकर विद्यामंदिर में।
- वर्तक नगर : सखी बूथ काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह और आदर्श केंद्र सिंघानिया स्कूल में।
- मुंब्रा-कौसा : सखी केंद्र एंजल पैराडाइज स्कूल और आदर्श केंद्र एम.एस. कॉलेज में।
- दिवा : न्यू गुरुकुल स्कूल और मेस्को स्कूल में सखी और आदर्श केंद्र बनाए गए हैं।

सुबह 6 बजे मॉक पोल, 7:30 बजे से वोटिंग

मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कल सुबह 6:00 बजे सभी 2013 मतदान केंद्रों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में 'मॉक पोल' (Mock Poll) किया जाएगा। इसके बाद ठीक सुबह 7:30 बजे से आम जनता के लिए वास्तविक मतदान शुरू होगा। प्रशासन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में बाहर आएं और लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लें।

महिला मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था

ठाणे मनपा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सुरक्षित माहौल देने के लिए चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। शहर में कुल 220 'महिला पोलिंग स्टेशन' बनाए गए हैं। विशेष रूप से कलवा, मुंब्रा और दिवा जैसे क्षेत्रों में धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए 'पर्दा-नशीन' (घूंघट वाली) महिलाओं के लिए पृथक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मुंब्रा वार्ड समिति में सर्वाधिक 125, दिवा में 79 और कलवा में 16 ऐसे विशेष बूथ तैयार किए गए हैं ताकि महिलाएं बिना किसी झिझक के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

गुलाबी रंग में रंगे 'सखी मतदान केंद्र'

महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए शहर में 11 'सखी मतदान केंद्र' (पिंक बूथ) स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों की खासियत यह है कि यहां पीठासीन अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी तक, पूरा स्टाफ महिलाओं का होगा। इन केंद्रों को गुलाबी रंग के गुब्बारों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। इसके अलावा, 10 जगहों पर 'आदर्श मतदान केंद्र' (Model Polling Stations) भी बनाए गए हैं, जहां मतदाताओं को सभी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। प्रशासन का मानना है कि इन कदमों से महिला वोटिंग प्रतिशत में भारी उछाल आएगा।

म्हाडा के 45 फीसदी मकान विजेताओं ने किए सरेंडर

- मंज़ूरी न मिलने से कोंकण बोर्ड के लिए नई चुनौती

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

कोंकण बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2025 में निकाली गई 5,285 घरों की लॉटरी के परिणामों ने बोर्ड की चिंता बढ़ा दी है। कुल 4,523 घोषित विजेताओं में से लगभग 45 फीसदी यानी 2,000 विजेताओं ने अपने घर सरेंडर (अस्वीकार) कर दिए हैं। यह एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिससे स्पष्ट होता है कि लॉटरी जीतने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग घरों का कब्जा लेने को तैयार नहीं हैं। बोर्ड को 762 घरों के लिए तो लॉटरी से पहले ही कोई आवेदन नहीं मिला था, जिससे खाली पड़े घरों की कुल संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

खाली घरों का संकट और भविष्य की रणनीति

लगातार बढ़ते रिजेक्शन रेट के कारण कोंकण बोर्ड के पास खाली पड़े घरों का स्टॉक अब 14,000 तक पहुँच गया है। जानकारों का मानना है कि घरों की ऊंची कीमतें, अनुपयुक्त लोकेशन और बुनियादी सुविधाओं की कमी इसके मुख्य कारण हैं। बोर्ड के पास वर्तमान में केवल 10% की वेटिंग लिस्ट उपलब्ध है, जिससे सरेंडर किए गए 2,000 घरों को भरना नामुमकिन लग रहा है। यदि वेटिंग लिस्ट के लोग भी घर नहीं लेते हैं, तो बोर्ड को इन फ्लैटों को अगले ड्रॉ में डालना होगा या फिर 'पहले आओ, पहले पाओ' (First Come, First Served) जैसी योजनाओं के जरिए बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा।

मनपा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बीएमसी चुनाव की वोटिंग से पहले शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। गोरेगांव से ठाकरे गुट के पूर्व नगरसेवक दिलीप शिंदे अपनी पत्नी के साथ शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बुधवार को मुंबई में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी में प्रवेश किया। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने दोनों का पार्टी में स्वागत किया और उनके आगे के राजनीतिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि दिलीप शिंदे के पार्टी में शामिल होने से पार्टी की ताकत बढ़ी है। उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में पार्टी को इससे बड़ा फायदा होगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री उदय सामंत, शिंदे गुट की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे और कई शिवसैनिक मौजूद थे।

तलिये लैंडस्लाइड पीड़ितों के लिए 147 घर मार्च में पूरे करने का प्लान

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

कोंकण बोर्ड ने जुलाई 2021 में तलिये और कोंधलकरवाड़ी में हुए भीषण भूस्खलन के बाद पीड़ितों के लिए 263 घरों की एक व्यापक पुनर्वास परियोजना शुरू की है। इस हादसे में 87 लोगों की जान चली गई थी और 66 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, म्हाडा ने 66 घरों का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और प्रभावित परिवारों को उनका कब्जा भी सौंप दिया है। शेष घरों में से 147 का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च 2026 तक पूरा कर रायगढ़ जिला कलेक्टर को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है।

परियोजना के सामने सबसे बड़ी बाधा 49 घरों के लिए ज़मीन की कमी है। म्हाडा के कोंकण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिला प्रशासन द्वारा ज़मीन उपलब्ध न कराए जाने के कारण इन घरों का निर्माण कार्य रुका हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए कोंकण बोर्ड के मुख्य अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को पुनः औपचारिक पत्र लिखकर ज़मीन की मांग की है। इसके जवाब में जिला कलेक्टर किसान जावले ने आश्वासन दिया है कि शेष घरों के लिए ज़मीन का निर्णय ले लिया गया है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर इसे म्हाडा को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

ठाणे के वार्ड 6 में 'नोट के बदले वोट' का आरोप

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे महानगरपालिका चुनाव के दौरान बुधवार को वार्ड नंबर 6 में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। आरोप है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद वहां मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे। दोपहर करीब 12:30 बजे हुई इस घटना की सूचना मिलते ही वर्तक नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एनसीआर (NCR) दर्ज कर ली है, लेकिन इस घटना ने स्थानीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। पुलिस ने इस मामले में 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People Act, 1951) की धारा 126(1), 126(2) और 126(3) के तहत मामला संज्ञान में लिया है। ये धाराएं चुनाव के दौरान अनुचित व्यवहार और वोटरों को प्रभावित करने से संबंधित हैं। हालांकि, जिन लोगों पर पैसे बांटने का आरोप लगा है, उन्होंने इन दावों को पूरी तरह से नकार दिया है। उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और यह विरोधियों द्वारा उन्हें फंसाने की एक राजनीतिक साजिश है। इसके बावजूद, पुलिस प्रशासन अभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि करने में जुटा है।

पुलिस ने दर्ज की एनसीआर

सिर्फ एनसीआर पर सवाल, जनता में आक्रोश

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई की प्रकृति पर उठाया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और विपक्षी दलों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने वाले इतने गंभीर आरोपों के बावजूद मामला सिर्फ एक एनसीआर (Non-Cognizable Report) तक ही क्यों सीमित रखा गया? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या लोकतंत्र बिकाऊ है और जब वोटिंग प्रक्रिया ही संदेह के घेरे में है, तो सख्त कार्रवाई कब होगी? आम जनता का कहना है कि यदि पैसे के दम पर वोट खरीदने के आरोपों की केवल खानापूर्ति वाली जांच होगी, तो आदर्श आचार संहिता का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

चुनाव आयोग की भूमिका पर टिकी निगाहें

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन अब पूरे राज्य की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हैं। सवाल यह है कि क्या आयोग इस मामले का स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेगा और एक कड़ा उदाहरण पेश करेगा? यह घटना न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी एक चेतावनी है। यदि समय रहते इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आम वोटर का चुनाव प्रक्रिया और आयोग की निष्पक्षता से भरोसा उठने का खतरा पैदा हो सकता है।

11 जगहों पर होगी ठाणे मनपा के आम चुनाव की गिनती

डीबीडी संवाददाता । ठाणे

ठाणे महानगरपालिका के आम चुनाव के लिए कल, 15 जनवरी 2026 को मतदान होगा। इसके तुरंत बाद, वोटों की गिनती शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू की जाएगी। मनपा आयुक्त और चुनाव अधिकारी सौरभ राव ने जानकारी दी है कि पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए 11 वार्ड-वाइज़ चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रत्येक वार्ड के लिए मतगणना स्थल निर्धारित कर दिए गए हैं, जहाँ प्रशासन ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी तकनीकी और सुरक्षा प्रबंध पूरे कर लिए हैं।

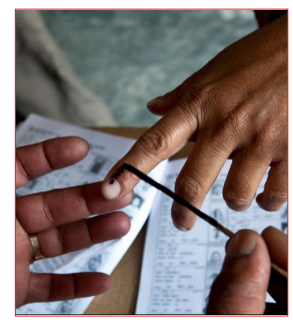

प्रमुख मतगणना केंद्र और उनके स्थान

विभिन्न प्रभाग समितियों के अंतर्गत आने वाले वार्डों के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। जैसे, वार्ड 1, 2, 3 और 8 के लिए हीरानंदानी एस्टेट स्थित न्यू होराइजन एजुकेशन सोसाइटी में व्यवस्था की गई है। इसी तरह, मुंब्रा और दिवा क्षेत्रों (वार्ड 26 से 33) की मतगणना मौलाना अबुल कलाम स्टेडियम, कौसा के विभिन्न मंजिलों और हॉल में होगी। नौपाड़ा-कोपरी के लिए विद्या प्रसारक मंडल (VPM) पॉलिटेक्निक कॉलेज और कलवा क्षेत्र के लिए सह्याद्री हाई स्कूल को चुना गया है। वर्तकनगर और उथलसर प्रभागों के लिए भी विशिष्ट जिमखाना और स्कूल हॉल आरक्षित किए गए हैं।

सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक अपील

मतगणना केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने और प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भारी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। सभी केंद्रों पर चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल अधिकृत अधिकारी, मतगणना कर्मचारी और उम्मीदवारों के प्रमाणित प्रतिनिधि ही इन केंद्रों में प्रवेश कर सकेंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ याचिका खारिज की

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के खिलाफ दायर याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायाधीश गौतम अंखड की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि चूंकि राज्य में चुनाव प्रक्रिया वर्तमान में जारी है, इसलिए अदालत इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह याचिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता अविनाश जाधव द्वारा दायर की गई थी, जिसमें राज्य भर में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे और इसे चुनौती दी गई थी। विवाद की जड़ राज्य की 65 से अधिक सीटें हैं, जहां किसी भी विपक्षी दल या निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया था। इसके चलते इन उम्मीदवारों के पार्षद बनने का रास्ता लगभग साफ हो गया था। हालांकि, विपक्ष द्वारा आपत्ति जताने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही इस मामले की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इन सभी उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से विजयी घोषित नहीं किया जाएगा।

किसी ने नामांकन रोकने की शिकायत नहीं की

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलों को अस्वीकार करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि याचिका में उठाई गई मांगों को इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने यह शिकायत दर्ज नहीं कराई है कि उसे नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया था। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि यदि ऐसी कोई अनियमितता की स्थिति बनती है, तो उसकी जांच करने का प्राथमिक अधिकार चुनाव आयोग के पास है, अदालत के पास नहीं। इसी आधार पर न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।

समयबद्ध जांच की थी मांग

फैसले के बाद मनसे नेता के वकील असीम सरोदे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे उच्च न्यायालय से इस मामले में समयबद्ध (Time-bound) जांच के आदेश की अपेक्षा कर रहे थे। उनका तर्क था कि चूंकि राज्य चुनाव आयोग ने पहले ही छानबीन के आदेश दे दिए हैं, इसलिए कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि यह जांच एक निश्चित समय सीमा में पूरी हो। अब याचिका खारिज होने के बाद चुनाव आयोग की जांच रिपोर्ट पर ही सभी की निगाहें टिकी हैं।

शरद पवार को झटका, पूर्व विधायक कदम ने छोड़ी पार्टी

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र में मनपा चुनाव से पहले शरद पवार की पार्टी एनसीपी को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार के कट्टर समर्थक और पूर्व विधायक रमेश कदम ने पार्टी छोड़ दी है। रमेश कदम चिपलून नगराध्यक्ष के चुनाव में हार गए थे. वे इससे नाखुश थे। पार्टी में सही जगह और सहयोग न मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। रमेश कदम 1984 से एनसीपी में थे। अजित पवार की बगावत के बाद एनसीपी के कई बड़े नेताओं ने अजित पवार का साथ दिया था, लेकिन रमेश कदम ने शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा। इस बीच राज्य में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों चुनावों का ऐलान भी हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 7 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। रमेश कदम का पार्टी का साथ छोड़ना, एनसीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

पश्चिम रेलवे

उद्यान विकास कार्य

मंडलीय रेल प्रबंधक (WA), पश्चिम रेलवे, 6वीं मंज़िल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई–400008 **ई-टेंडर सूचना संख्या: BCT/25-26/295, दिनांक 13.01.2026** आमंत्रित करते हैं। **कार्य एवं स्थान:** ज़ोन हॉर्टिकल्चर: चर्चगेट–विरार खंड में उद्यानों का विकास—जिसमें उर्वरक, खाद, बीज, पौधे, फूलों के गमले, बागवानी उपकरण एवं सहायक सामग्री की आपूर्ति शामिल है। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹30,97,260/- **ईएमडी :** ₹62,000/- **निविदा जमा करने की तिथि एवं समय:** 06.02.2026 को 15:00 बजे तक। **निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** 06.02.2026 को 15:30 बजे। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर जाएँ। **1006**

लाइक करें: facebook.com/WesternRly

मुंबई में तीन दिन 'ड्राई डे'

हाई कोर्ट ने शराबबंदी पर रोक लगाने से किया इनकार, याचिका खारिज

डीबीडी संवाददाता । मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा घोषित तीन दिवसीय शराबबंदी (Dry Day) के आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने शराब विक्रेताओं के संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मुंबई में आज (14 जनवरी) से लेकर 16 जनवरी तक शराबबंदी का आदेश सख्ती से लागू रहेगा और मदिरा प्रेमियों को अगले तीन दिनों तक इंतजार करना होगा।

राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने और शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया है। आदेश के अनुसार, 14 जनवरी से 16 जनवरी, 2026 तक मुंबई में शराब की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस अवधि में मतदान से पूर्व की शाम, 15 जनवरी को मतदान का पूरा दिन और उसके बाद मतगणना का दिन शामिल है। प्रशासन का तर्क है कि चुनाव के दौरान शांति भंग होने की आशंका को रोकने के लिए यह एहतियाती कदम उठाना अनिवार्य है।

आर्थिक नुकसान की दलील खारिज

शराब विक्रेताओं के एक संघ (Association of Liquor Sellers) ने सरकार के इस आदेश को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि लगातार तीन दिनों तक शराब की बिक्री पर रोक लगाने से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, जो उनके व्यवसाय के लिए न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि या तो प्रतिबंध की अवधि को कम किया जाए या इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर विस्तृत जांच और विचार की आवश्यकता है, इसलिए ऐन मौके पर शराबबंदी के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय की है। कोर्ट ने कहा कि व्यापक जनहित और चुनाव की शुचिता को देखते हुए फिलहाल प्रशासन का आदेश प्रभावी रहेगा।

▸▸वर्ष : 34 ▸▸अंक : 309 ▸▸मुंबई, गुरुवार, 15 जनवरी 2026 ▸▸RNI: MAHHIN/49994/91 ▸▸मूल्य : 3 रुपए ▸▸epaper.dobajedopahar.com ▸▸संपादक : अरुण लाल ▸▸संरक्षक : एन. के. पुरोहित

DBD

दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

893 वार्डों में 2,869 सीटों के लिए लड़ाई

मुंबई में 1,700 और पुणे में 1,166 उम्मीदवार मैदान में

आज होगा 'महा' मतदान

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र में आज होने वाले 29 नगर निगमों के चुनावों के लिए मंच सज चुका है। पूरे देश की निगाहें मुंबई पर टिकी हैं, जहां देश की सबसे अमीर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) पर नियंत्रण के लिए एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति, धन-बल से भरपूर इस निकाय को अपने कब्जे में लेने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संयुक्त मोर्चे से सीधी टक्कर ले रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने पूरे राज्य में व्यापक प्रचार किया, जबकि ठाकरे बंधुओं ने अपना ध्यान मुंबई, ठाणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर पर केंद्रित रखा। मुंबई को छोड़कर, अन्य 28 शहरी निकायों में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू है।

29 महानगरपालिकाओं में आज होगा मतदान

3.48 करोड़ मतदाता करेंगे 15,931 उम्मीदवारों का फैसला

893 वार्डों में 2,869 सीटों के लिए मतदान

राज्य भर में 893 वार्डों में 2,869 सीटों के लिए मतदान 15 जनवरी को सुबह 7 .30 बजे शुरू होगा और शाम 5 .30 बजे समाप्त होगा। कुल 3 .48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें मुंबई में 1,700 और पुणे में 1,166 उम्मीदवार मैदान में हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मुंबई भर में वरिष्ठ अधिकारियों सहित 25,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

महापौर की कुर्सी पर धर्म का तड़का

मुंबई के महापौर पद की दौड़ चुनाव प्रचार का केंद्रबिंदु बन गई है, जिसमें सांप्रदायिक रंग भी देखने को मिला। भाजपा ने दावा किया कि शिवसेना (यूबीटी) की जीत से शहर को एक 'मुस्लिम महापौर' मिल सकता है। इसका खंडन करते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मतदाताओं को 'मराठी महापौर' देने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी अपनी रैलियों में जोर देकर कहा कि मुंबई का महापौर 'हिंदू और मराठी' ही होगा, जिससे ध्रुवीकरण की कोशिशें साफ नजर आईं।

बेमेल गठबंधन

चुनावों से ठीक पहले एक बड़े राजनीतिक मोड़ में, दो दशकों बाद बिछड़े हुए चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे मराठी वोटों को एकजुट करने के प्रयास में फिर से एक साथ आए हैं। उन्होंने अपनी पुरानी प्रतिद्वंद्विता को भुलाकर 'मराठी अस्मिता' को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया है। दूसरी ओर, प्रतिद्वंद्वी एनसीपी गुटों ने पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में स्थानीय गठबंधन बनाकर सबको चौंका दिया है। इस चुनाव में विपक्षी कांग्रेस ने अपने महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के सहयोगियों - शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की एनसीपी (एसपी) - की छाया से बाहर निकलने का फैसला किया है। मुंबई में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) और राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ गठबंधन किया है, जबकि नागपुर में वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने मुंबई में 143 और राज्य के शेष हिस्सों में 1,263 उम्मीदवार उतारे हैं।

छत्रपति संभाजीनगर: उम्मीदवारों की भारी भीड़

मराठवाड़ा के इस प्रमुख शहर में 117 सीटों के लिए सर्वाधिक 1,267 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो राज्य में एक रिकॉर्ड है। यहाँ मतदाताओं की संख्या 11 .18 लाख है। यहाँ गठबंधन पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। कांग्रेस ने वंचित के साथ गठबंधन किया है, लेकिन भाजपा, शिवसेना, शिवसेना (यूबीटी), एआईएमआईएम और एनसीपी सभी स्वतंत्र रूप से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

नवी मुंबई: समीकरण सबसे अलग

नवी मुंबई में 111 सीटों के लिए 500 उम्मीदवार चुनावी जंग में हैं। यहाँ 9 .48 लाख मतदाता अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ के समीकरण सबसे अलग हैं। भाजपा और शिंदे सेना अलग-अलग लड़ रही हैं। वहीं, मनसे और उद्धव सेना ने गठबंधन किया है। दोनों एनसीपी गुट (शरद और अजित पवार) भी यहाँ एक-दूसरे के खिलाफ स्वतंत्र रूप से मैदान में हैं।

पुणे: सांस्कृतिक राजधानी में कड़ा मुकाबला

पुणे महानगरपालिका (PMC) में 165 सीटों के लिए 1,955 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ 35 .51 लाख मतदाताओं का विशाल आधार शहर की नई सरकार चुनेगा। पिछले चुनावों में यहाँ 53 .50% वोटिंग हुई थी। इस बार भाजपा ने आरपीआई (आठवले) के साथ गठबंधन किया है, जबकि एनसीपी के दोनों गुट एक साथ हैं। वहीं, एक दिलचस्प समीकरण में कांग्रेस, उद्धव सेना और मनसे का गठबंधन मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहा है।

नागपुर: उपराजधानी में सत्ता का संघर्ष

महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में 38 वार्डों की 151 सीटों के लिए 993 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ 24 .83 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भाजपा ने यहाँ शिंदे सेना के साथ मजबूत गठबंधन किया है। दूसरी ओर, विपक्ष बिखरा हुआ है जहाँ कांग्रेस, उद्धव सेना, एनसीपी (शरद पवार), एनसीपी (अजित पवार) और वंचित बहुजन अघाड़ी अलग-अलग या निर्दलीय के रूप में चुनौती पेश कर रहे हैं।

पिंपरी-चिंचवड: उद्योग नगरी की जंग

आईटी और औद्योगिक हब पिंपरी-चिंचवड में 128 सीटों के लिए 692 उम्मीदवार मैदान में हैं। 17 .13 लाख मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में भाजपा-आरपीआई (आठवले) का गठबंधन है। यहाँ एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में एनसीपी (अजित पवार) और एनसीपी (शरद पवार) एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, उद्धव सेना ने मनसे के साथ हाथ मिलाया है, जबकि शिंदे सेना और कांग्रेस अलग-अलग लड़ रहे हैं।

ठाणे: उपमुख्यमंत्री के गढ़ में अग्निपरीक्षा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृहक्षेत्र ठाणे में कुल 33 प्रभागों में 131 नगरसेवकों का चुनाव कराया जाना है। कुल 2013 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। 649 उम्मीदवार हैं। ठाणे मनपा क्षेत्र में 16,49,869 मतदाता हैं, जिनमें से 8 .63,878 पुरुष और 7,85,830 मुदिलाएं और 159 तृतीयपंथी हैं। इस बार मतदाता यहाँ पिछले 58 .08% मतदान के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ भाजपा और शिंदे सेना का गठबंधन है।

नासिक: पंचवटी में पंचकोणीय संघर्ष

नासिक के 31 वार्डों की 122 सीटों के लिए 735 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहाँ 13 .60 लाख मतदाता हैं और पिछला मतदान प्रतिशत 61% रहा था। यहाँ समीकरण काफी उलझे हुए हैं। उद्धव सेना, मनसे, राकांपा (शरद पवार) और कांग्रेस का एक महा-गठबंधन है, जबकि शिंदे सेना ने एनसीपी के साथ हाथ मिलाया है और भाजपा स्वतंत्र रूप से निर्दलीयों के साथ मैदान में है।

कल्याण-डोम्बिवली: उपनगरों की सियासत

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में 122 सीटों के लिए 488 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मतदाताओं की संख्या 14 .24 लाख के पार है। सत्ताधारी पक्ष से भाजपा, शिंदे सेना और आरपीआई का गठबंधन है। विपक्ष में उद्धव सेना और मनसे एक साथ आए हैं, जबकि एनसीपी (अजित पवार) यहाँ अपनी अलग राह पर चलते हुए निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ ताल ठोक रही है।

सोलापुर : टेक्सटाइल सिटी में गठबंधन का पेंच

सोलापुर में 102 सीटों पर 564 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 9 .24 लाख मतदाता पंजीकृत हैं। यहाँ शिंदे सेना और एनसीपी का गठबंधन है। दूसरी तरफ, कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार) और शिवसेना (यूबीटी) का एक मजबूत गठबंधन (MVA) बना है। भाजपा यहाँ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़कर अपनी ताकत का परीक्षण कर रही है।

भिवंडी-निज़ामपुर : पावरलूम सिटी का मिजाज

भिवंडी में 90 सीटों के लिए 438 उम्मीदवार हैं और 6 .69 लाख मतदाता हैं। यहाँ भाजपा और शिंदे सेना का गठबंधन है। उद्धव सेना और मनसे भी साथ हैं। लेकिन यहाँ समाजवादी पार्टी, एनसीपी (अजित पवार) और एनसीपी (शरद पवार) के अलग-अलग लड़ने से मुस्लिम वोटों का बिखराव तय माना जा रहा है।

वसई-विरार : बहुजन विकास अघाड़ी का प्रभाव

पालघर जिले के इस प्रमुख नगर निगम में 115 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जहाँ 11 .27 लाख मतदाता मतदान करेंगे। यहाँ का चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहा है। भाजपा और शिंदे सेना गठबंधन में हैं, लेकिन उन्हें बहुजन विकास अघाड़ी और मनसे के संयुक्त गठबंधन से कड़ी टक्कर मिल रही है। एनसीपी (अजित पवार) और कांग्रेस यहाँ अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं।

कोल्हापुर : राजनीतिक अखाड़े में दंगल

कोल्हापुर में 81 सीटों के लिए 327 प्रत्याशी हैं। यहाँ का पिछला मतदान 68 .85% काफी अच्छा रहा था। यहाँ महायुति (बीजेपी, शिंदे सेना, अजित पवार एनसीपी और आठवले गुट) एक साथ है।

सांगली-मिराज-कुपवाड़ : पश्चिमी महाराष्ट्र की साख

इस नगर निगम में 78 सीटों के लिए 381 उम्मीदवार हैं और 4 .30 लाख मतदाता हैं। यहाँ भाजपा स्वतंत्र रूप से लड़ रही है, जो एक बड़ा जोखिम है। कांग्रेस और एनसीपी (एसपी) का गठबंधन है, जबकि उद्धव सेना ने मनसे के साथ साझेदारी की है।

अकोला : विदर्भ का रण

अकोला में 80 सीटों के लिए 630 उम्मीदवार हैं और 5 .50 लाख मतदाता हैं। यहाँ भाजपा और एनसीपी (अजित पवार) का गठबंधन है। कांग्रेस ने शरद पवार की एनसीपी के साथ हाथ मिलाया है। उद्धव सेना और मनसे साथ हैं, लेकिन शिंदे सेना अलग लड़ रही है।

नांदेड़-वाघाला: सिखों की नगरी में सियासी जंग

नांदेड़ में 81 सीटों के लिए 491 उम्मीदवार हैं। 5 .01 लाख मतदाता हैं। यहाँ उद्धव सेना, मनसे और राकांपा (शरद पवार) स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं। शिंदे सेना और एनसीपी (अजित पवार) का गठबंधन केवल 16 सीटों पर सीमित है। कांग्रेस ने यहाँ वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन कर एक नई रणनीति अपनाई है।

पनवेल: रायगढ़ का मुकाबला

पनवेल में 78 सीटों के लिए 246 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं की संख्या लगभग 1 .29 लाख है। यहाँ मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा के गढ़ को बचाने का है। विपक्ष यहाँ स्थानीय मुद्दों और विकास के एजेंडे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। उम्मीदवारों की कम संख्या यह बताती है कि मुकाबला सीधा और कड़ा है।

धुले: खानदेश की राजनीति

धुले में 74 सीटों के लिए 316 उम्मीदवार हैं और 4 .30 लाख मतदाता हैं। भाजपा यहाँ अकेले लड़ रही है। शिंदे सेना और एनसीपी (अजित पवार) का गठबंधन है। सबसे बड़ा गठबंधन विपक्ष का है, जहाँ उद्धव सेना, एनसीपी (शरद पवार), कांग्रेस और मनसे एक साथ आए हैं। एआईएमआईएम भी यहाँ एक महत्वपूर्ण कारक है।

घोषणापत्रों में लोकलुभावन वादे

सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। महायुति और शिवसेना (यूबीटी)-मनसे दोनों के घोषणापत्रों में महिलाओं के लिए लोकलुभावन वादे प्रमुखता से शामिल हैं। महायुति ने बीईएसटी (BEST) बस यात्रा में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत की छूट का वादा किया है। वहीं, ठाकरे बंधुओं ने महिला घरेलू सहायिकाओं के लिए 1,500 रुपये का मासिक भत्ता और 700 वर्ग फुट तक के घरों पर संपत्ति कर में पूर्ण छूट का आश्वासन दिया है।इसके विपरीत, कांग्रेस के घोषणापत्र का फोकस थोड़ा अलग है। पार्टी ने मुंबई के प्रदूषण से निपटने, बीईएसटी बेड़े को उन्नत करने और शहर की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने को प्राथमिकता दी है। तेलंगाना के मंत्री मोहम्मद अज़हरुद्दीन, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और तमिलनाडु भाजपा नेता के अन्नामलाई जैसे स्टार प्रचारकों ने भी अपने-अपने दलों के लिए माहौल बनाने की कोशिश की है।

वर्चस्व की अग्निपरीक्षा

▸▸राज्य नेतृत्व और क्षेत्रीय दलों की कड़ी अग्निपरीक्षा

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

देश की सबसे अमीर और प्रतिष्ठित महानगरपालिका बीएमसी के चुनाव इस बार शिवसेना के 25 साल के वर्चस्व की सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा हैं, जहां पार्टी में विभाजन के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे गुट को भाजपा नेतृत्व वाले 'महायुति' गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है। 1.03 करोड़ मतदाताओं और 227 सीटों वाले इस सियासी दंगल में 1,700 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं; एक तरफ भाजपा (137 सीट) ने शिंदे सेना (90 सीट) और आरपीआई के साथ मोर्चा संभाला है, तो दूसरी तरफ उद्धव सेना (163 सीट) ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मनसे (52 सीट) और शरद पवार की एनसीपी के साथ नया गठजोड़ तैयार किया है, जबकि कांग्रेस (143 सीट) और अजित पवार की एनसीपी (94 सीट) अलग-अलग समीकरण साधने में जुटी हैं, जिससे यह मुकाबला बेहद दिलचस्प और बहुकोणीय हो गया है।

केंद्रीय हस्तक्षेप नहीं, फडणवीस-चव्हाण की साख दांव पर

भाजपा के शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी ये नतीजे बेहद अहम हैं, क्योंकि यह पहला ऐसा बड़ा चुनाव है जो पूरी तरह से राज्य नेतृत्व के भरोसे लड़ा जा रहा है। लोकसभा और विधानसभा में जहां केंद्रीय कमान की रणनीति हावी थी, वहीं इस बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण की रणनीतियों पर दांव लगाया गया है। ऐसे में जीत का सेहरा या हार का ठीकरा सीधे तौर पर राज्य नेतृत्व के सिर पर होगा। इन नतीजों से ही यह तय होगा कि भविष्य में भाजपा और शिंदे सेना के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे और पार्टी के भीतर फडणवीस का कद क्या होगा।

ठाकरे बंधुओं का अस्तित्व और कांग्रेस-एनसीपी के भविष्य का फैसला

विपक्ष के लिए भी यह चुनाव 'करो या मरो' की स्थिति है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना मुंबई में शिवसेना के मूल वोट बैंक को कितना एकजुट रख पाता है, इसका फैसला इन नतीजों से हो जाएगा। यह चुनाव तय करेगा कि मुंबई में ठाकरे ब्रांड का वजूद कितना शेष है। दूसरी ओर, कांग्रेस को अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए गठबंधन की समीक्षा करनी होगी। वहीं, शरद पवार और अजित पवार के गुटों के लिए भी यह मंथन का समय होगा कि उन्हें भविष्य में अलग-अलग राह पर चलना है या फिर एक बार फिर एकजुटता की गुंजाइश बाकी है।

अमरावती : विदर्भ में बहुकोणीय लड़ाई

अमरावती की 87 सीटों के लिए 661 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6 .77 लाख मतदाता यहाँ फैसला करेंगे। कांग्रेस एक मोर्चे का नेतृत्व कर रही है। उद्धव सेना और मनसे यहाँ भी साथ हैं। शिंदे सेना ने बच्चू कडू की प्रहार पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो एक अहम कारक है। एनसीपी (शरद पवार) ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हाथ मिलाया है, जबकि वंचित का अपना अलग फोरम है।

मालेगांव : मुस्लिम बहुल क्षेत्र के समीकरण

नासिक जिले के मालेगांव में 84 सीटों के लिए 301 उम्मीदवार हैं, जहाँ 5 .17 लाख मतदाता मतदान करेंगे। यहाँ का चुनाव बेहद दिलचस्प है। भाजपा, शिंदे सेना, कांग्रेस और एनसीपी (अजित पवार) सभी अलग-अलग लड़ रहे हैं। एनसीपी (शरद पवार) ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है, जो एक बड़ा कदम है। वहीं, 'महाराष्ट्र पार्टी (इस्लाम)' के बैनर तले कई उम्मीदवार स्वतंत्र लड़ रहे हैं।

जलगांव : गोल्ड सिटी में चमक किसकी?

जलगांव में 75 सीटों के लिए 321 उम्मीदवार हैं और 7 .30 लाख मतदाता हैं। यहाँ महायुति (भाजपा, शिंदे सेना, अजित पवार एनसीपी) पूरी तरह एकजुट है। विपक्ष में उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी का गठबंधन है, जबकि कांग्रेस ने वंचित के साथ हाथ मिलाया है।

लातूर : देशपांडे और पाटिल की विरासत

लातूर में 70 सीटों के लिए 359 उम्मीदवार हैं और 3 .75 लाख मतदाता हैं। यहाँ कांग्रेस और वंचित का गठबंधन एक मजबूत ताकत बनकर उभरा है। इसके विपरीत, भाजपा, दोनों एनसीपी गुट और दोनों शिवसेना गुट स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला बहुकोणीय हो गया है।

अहिल्यानगर : नाम बदलने के बाद पहला चुनाव

अहमदनगर (अब अहिल्यानगर) में 67 सीटों के लिए 283 उम्मीदवार हैं। यहाँ का पिछला मतदान 68% रहा था, जो मतदाताओं की जागरूकता को दर्शाता है। शहर का नाम बदलने के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है, इसलिए अस्मिता का

इचलकरंजी : 'मैनचेस्टर' का पहला निगम चुनाव

नवगठित इचलकरंजी नगर निगम में 65 सीटों के लिए 302 प्रत्याशी हैं। यहाँ पिछला मतदान रिकॉर्ड 76 .50% के साथ राज्य में सर्वाधिक रहा है। भाजपा, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी का गठबंधन है। विपक्ष में कांग्रेस, मनसे और शरद पवार की एनसीपी साथ हैं। वंचित और आप का भी यहाँ गठबंधन है।

परभनी और चंद्रपुर : विदर्भ-मराठवाड़ा का अंतिम चरण

परभनी में 65 सीटों के लिए 411 उम्मीदवार और 2 .61 लाख मतदाता हैं। वहीं, चंद्रपुर में 66 सीटों के लिए 2 .99 लाख मतदाता फैसला करेंगे। चंद्रपुर में भाजपा-शिंदे सेना गठबंधन का मुकाबला उद्धव सेना-वंचित गठबंधन से है। कांग्रेस और अन्य दल यहाँ निर्दलीय रूप से लड़कर मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं।

मीरा-भाईंदर में महायुति में ही लड़ाई

24 वार्डों की 95 सीटों के लिए 434 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 .19 लाख मतदाता चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। महायुति के दो घटक दल बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने सर्वाधिक 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी 81 सीटों पर ताल ठोक रही है। वहीं, विपक्ष में एक नया समीकरण साधते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) ने 56 और राज ठाकरे की मनसे ने 11 सीटों पर गठबंधन के तहत प्रत्याशी खड़े किए हैं। इसके अलावा, कांग्रेस 32, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 33 और शरद पवार की एनसीपी 14 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है, जिससे इस क्षेत्र में मुकाबला बेहद कड़ा और बहुकोणीय हो गया है।

उल्हासनगर : कालानी परिवार की भूमिका

उल्हासनगर में 78 सीटों के लिए 596 उम्मीदवार हैं और 4 .39 लाख मतदाता हैं। यहाँ की राजनीति हमेशा स्थानीय क्षत्रपों पर निर्भर रही है। शिंदे सेना ने ओमी कालानी और साईं पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिससे उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। विपक्ष में कांग्रेस, उद्धव सेना और मनसे का एक संयुक्त गठबंधन उन्हें टक्कर दे रहा है।

जालना : रिकॉर्ड तोड़ उम्मीदवारों की संख्या

जालना नगर निगम में 65 सीटों के लिए रिकॉर्ड 2,016 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा है। यहाँ 2 .44 लाख मतदाता मतदान करेंगे। इतने अधिक उम्मीदवारों के कारण हर वार्ड में मतों का भारी बिखराव तय है और हार-जीत का अंतर बेहद कम रहने की संभावना है।

संपादकीय

मतदान जिम्मेदारी है

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सहित महाराष्ट्र की अन्य महानगर पालिकाओं—जैसे पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड़, नागपुर, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर—के चुनाव केवल नगर निकायों की औपचारिक प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि यह शहरी लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। विशेष रूप से बीएमसी का चुनाव तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के भविष्य का जनादेश माना जाता है। एशिया की सबसे समृद्ध महानगरपालिका होने के बावजूद बीएमसी और अन्य महानगर पालिकाओं में नागरिक भागीदारी लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। यदि पिछले चुनावों के मतदान आंकड़ों पर नजर डालें, तो एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है। 2017 के बीएमसी चुनाव में मतदान प्रतिशत लगभग 55 प्रतिशत रहा, जबकि 2012 में यह करीब 52 प्रतिशत था। यानी लगभग 45 प्रतिशत मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए। यही प्रवृत्ति महाराष्ट्र की अन्य महानगर पालिकाओं में भी देखने को मिलती है। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ जैसी शिक्षित और आईटी हब कही जाने वाली नगरपालिकाओं में भी मतदान प्रतिशत अक्सर 50 से 60 प्रतिशत के बीच ही सिमट जाता है। यह स्थिति तथाकथित शहरी जागरूकता पर सवाल खड़े करती है। यह और भी चिंताजनक तब हो जाता है जब हम यह समझते हैं कि इन महानगर पालिकाओं के पास अरबों रुपये का बजट और व्यापक प्रशासनिक अधिकार होते हैं। सड़क, जलापूर्ति, कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे जीवन से जुड़े विषय सीधे महानगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके बावजूद यदि आधी आबादी मतदान से दूर रहती है, तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने जैसा है। महानगर पालिका चुनावों में कम मतदान का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि संगठित, सीमित और प्रभावशाली समूह निर्णय प्रक्रिया पर हावी हो जाते हैं। मुंबई, पुणे या ठाणे के कई वार्डों में जीत-हार का अंतर कुछ सौ या कुछ हजार वोटों तक सीमित रहता है। ऐसे में सामान्य नागरिक का मतदान न करना, उसके भविष्य से जुड़े फैसलों को दूसरों के हाथों सौंप देना है। लोकतंत्र में यह स्थिति किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं मानी जा सकती। युवा मतदाताओं की भूमिका सभी महानगर पालिकाओं में निर्णायक हो सकती है। मुंबई, पुणे, नवी मुंबई और पिंपरी-चिंचवड़ जैसे शहरों में 18 से 40 वर्ष की आबादी बड़ी संख्या में है। लेकिन मतदान के दिन यही वर्ग सबसे अधिक उदासीन नजर आता है। सोशल मीडिया पर शिकायतें और प्रशासनिक आलोचना करना आसान है, पर मतदान केंद्र तक पहुंचना नागरिक जिम्मेदारी का वास्तविक प्रमाण है। यदि युवा वर्ग सक्रिय रूप से मतदान करे, तो रोजगार, परिवहन, पर्यावरण और शहरी नियोजन जैसे मुद्दे स्वतः राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में आ जाएंगे। महानगर पालिका चुनाव सामाजिक संतुलन का भी आईना होते हैं। महानगरों में झुग्गी-बस्तियों से लेकर उच्च वर्गीय रिहायशी परिसरों तक समाज की हर परत मौजूद है। यदि कमजोर और वंचित वर्ग मतदान से दूर रहता है, तो नीतियां स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली वर्गों के हित में झुक जाती हैं। मतदान ही वह लोकतांत्रिक माध्यम है, जिसके जरिए हर वर्ग अपनी प्राथमिकताओं को सत्ता तक पहुंचा सकता है। यह सच है कि महाराष्ट्र की कई महानगर पालिकाओं पर भ्रष्टाचार, ठेकेदारी व्यवस्था और पारदर्शिता की कमी को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन इन समस्याओं का समाधान मतदान से दूरी नहीं, बल्कि अधिक जागरूक, निर्भीक और निर्णायक मतदान है। जब नागरिक गलत प्रतिनिधियों को सत्ता से बाहर करता है, तभी व्यवस्था में सुधार की वास्तविक संभावना बनती है।

मुंबई की सियासी बिसात

बदलते समीकरणों का नया गणित

धीरज सिंह
समाचार संपादक

महानगरपालिका (BMC) का आगामी चुनाव महज 227 पार्षदों के चयन का स्थानीय चुनाव नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र की राजनीति की भविष्यवाणियां लिखने वाला एक निर्णायक महासंग्राम बन चुका है। देश की सबसे अमीर महानगरपालिका मानी जाने वाली BMC का वार्षिक बजट लगभग 74,000 करोड़ के पार जा चुका है—एक ऐसी राशि जो सिक्किम, गोवा और मिजोरम जैसे कई भारतीय राज्यों के कुल वार्षिक बजट से भी अधिक है। यही कारण है कि इस चुनाव में सिर्फ विकास के वादे नहीं, बल्कि सत्ता, संसाधन और राजनीतिक अस्तित्व का भविष्य दांव पर लगा है। 2017 के BMC चुनाव के परिणाम एक कड़े मुकाबले की गवाही देते हैं। उस समय अविभाजित शिवसेना ने 84 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा ने उसे कड़ी टक्कर देते हुए 82 सीटों पर कब्जा किया था। कांग्रेस 31, एनसीपी 9, समाजवादी पार्टी 6 और AIMIM 2 सीटों पर सिमट गई थी। उस समय भाजपा और शिवसेना अलग-अलग लड़े थे, लेकिन आज स्थितियां पूरी तरह भिन्न हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया—चाहे वह महाविकास अघाड़ी (MVA) का गठन हो, शिवसेना का दो फाड़ होना हो या फिर एनसीपी में टूट—उसने मुंबई के मतदाताओं के सामने विकल्पों का एक नया और जटिल संसार खड़ा कर दिया है। मुंबई की राजनीति की धुरी हमेशा से 'मराठी मानुस' और उसकी अस्मिता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। मुंबई की लगभग 35 से 38 प्रतिशत आबादी मराठी भाषी है। दादर, परेल, शिवडी, वरळी, भांडुप, विक्रोली और घाटकोपर जैसे इलाकों में उद्धव ठाकरे के प्रति एक 'मूक सहानुभूति' साफ दिखाई देती है। जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवसेना का नाम व चुनाव चिह्न हाथ से गया, उसने मराठी समाज के एक बड़े वर्ग को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया है। उद्धव ठाकरे इस चुनाव में इसी 'विक्टिम कार्ड' और मराठी गौरव को अपनी ढाल बना रहे हैं। दूसरी ओर, राज ठाकरे की मनसे (MNS) भी सक्रिय है, जो मराठी वोटों के विभाजन का कारण बन सकती है। लेकिन, जमीनी स्तर पर यह देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की बदली हुई छवि—जो अब अधिक समावेशी और उदार नजर आती है—उन्हें केवल कट्टर शिवसैनिकों तक सीमित नहीं रख रही। मुंबई का मुस्लिम मतदाता, जिसकी आबादी लगभग 20-22 प्रतिशत है, इस बार अभूतपूर्व रणनीतिक भूमिका में है। शहर के करीब 50 से अधिक वार्डों में मुस्लिम वोट हार-जीत का फैसला करने की क्षमता रखते हैं। परंपरागत रूप से यह वोट बैंक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बंटता रहा है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के रुझानों ने संकेत दिया है कि इस बार मुस्लिम समुदाय का झुकाव उस दल की ओर अधिक है जो भाजपा को सीधी टक्कर देने में सक्षम है। हैरानी की बात यह है कि कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना (UBT) अब मुस्लिम इलाकों में स्वीकार्य हो रही है। उद्धव ठाकरे द्वारा 'धर्मनिरपेक्षता' और 'संविधान' की बात करना उन्हें एक नया आधार दे रहा है। यदि यह समीकरण बैठ गया, तो मुंबई के वार्डों में गणित पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा और सामाजिक आधार मुंबई में बेहद चट्टानी है। मुंबई के हिंदी भाषी मतदाता (करीब 25-28 प्रतिशत) का लगभग 75–80 प्रतिशत हिस्सा भाजपा के साथ मजबूती से खड़ा है। इसके साथ ही गुजराती, राजस्थानी और जैन समुदायों का समर्थन भाजपा को आर्थिक और चुनावी दोनों स्तरों पर मजबूती देता है। भाजपा इस बार 'विकास' और 'डबल इंजन सरकार' के नैरेटिव पर दांव लगा रही है। कोस्टल रोड, मेट्रो नेटवर्क का विस्तार, नवी मुंबई एयरपोर्ट और ट्रांस-हार्बर लिंक जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को भाजपा अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। कॉर्पोरेट जगत और मध्यम वर्ग, जो स्थिरता और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देता है, वह भाजपा की ओर झुकाव रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और अमित शाह की चुनावी रणनीति भाजपा के लिए सबसे बड़ा संबल है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए यह चुनाव उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता की अग्निपरीक्षा है। उन्हें यह साबित करना है कि वह केवल 'विधायकों के नेता' नहीं, बल्कि 'जनता के नेता' भी हैं। 'वर्षा' बंगले के दरवाजे आम लोगों के लिए खोलना और मुंबई के सुंदरीकरण (Beautification) पर जोर देना उनकी रणनीति का हिस्सा है। शिंदे गुट उन इलाकों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है जो कभी शिवसेना का अभेद्य किला माने जाते थे। हालांकि, भाजपा और शिंदे गुट के बीच सीटों का बंटवारा और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मुंबई का यह चुनाव दरअसल 'भाजपा की चुनावी मशीनरी' बनाम 'उद्धव ठाकरे की सहानुभूति' का संघर्ष है। जहां भाजपा के पास अपार संसाधन, पन्ना प्रमुखों की फौज और केंद्र की शक्ति है, वहीं विपक्षी खेमे के पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा मुंबई है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा स्थानीय चुनावों में भी असर डाल सकता है।

जीवन मंत्र

शुद्धता: चेतना, स्वास्थ्य और संतुलन का आधार

शुद्धता का अर्थ संन्यास नहीं, बल्कि सजग जीवन है। जब मनुष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर सजग हो जाता है, तब उसकी जीवन ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। शुद्धता से उत्पन्न यह ऊर्जा ही मनुष्य को स्वस्थ, संतुलित और जागरूक बनाती है।

शुद्धता केवल बाहरी स्वच्छता का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन ऊर्जा का मूल आधार है। जब मनुष्य शुद्धता को केवल स्नान, वस्त्र या आचरण तक सीमित कर देता है, तब वह उसके गहरे अर्थ को समझ नहीं पाता। वास्तविक शुद्धता विचार, भावना, वाणी और कर्म—इन चारों के संतुलन से उत्पन्न होती है। जहां शुद्धता होती है, वहीं जीवन ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। शरीर की शुद्धता स्वास्थ्य को जन्म देती है। स्वच्छ शरीर में रोगों का प्रवेश कठिन होता है और ऊर्जा का क्षय कम होता है। लेकिन शरीर से भी अधिक महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता। दूषित विचार, ईर्ष्या, द्वेष, भय और क्रोध मन की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब मन शुद्ध होता है, तब निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। शुद्ध मन ही सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बडा स्रोत है। वाणी की शुद्धता भी जीवन ऊर्जा को सशक्त बनाती है। कटु, असत्य और अपमानजनक शब्द ऊर्जा को बाहर की ओर बिखेर देते हैं, जबकि सत्य, मधुर और संयमित वाणी भीतर की शक्ति को संचित करती है। इसी प्रकार कर्म की शुद्धता मनुष्य को आत्मविश्वास देती है। जब कर्म छल, लोभ और स्वार्थ से मुक्त होते हैं, तब अंतर्मन शांत रहता है और ऊर्जा निरंतर बनी रहती है। शुद्धता का संबंध प्रकृति से भी गहरा है। स्वच्छ जल, शुद्ध वायु और सात्विक आहार जीवन शक्ति को पोषित करते हैं।

जिस प्रकार दूषित जल शरीर को बीमार करता है, उसी प्रकार दूषित विचार आत्मा को दुर्बल बना देते हैं। इसलिए शुद्धता का अभ्यास जीवन के हर स्तर पर आवश्यक है। शुद्धता का अर्थ संन्यास नहीं, बल्कि सजग जीवन है। जब मनुष्य अपने विचारों, शब्दों और कर्मों पर सजग हो जाता है, तब उसकी जीवन ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। शुद्धता से उत्पन्न यह ऊर्जा ही मनुष्य को स्वस्थ, संतुलित और जागरूक बनाती है। वास्तव में, शुद्धता जीवन ऊर्जा को जागृत करने की सबसे सरल और प्रभावशाली साधना है।

शख्सियत

मार्टिन लूथर किंग जूनियर

अहिंसा, समानता और मानव गरिमा के महान प्रहरी

"अंधकार अंधकार को नहीं मिटा सकता, यह काम केवल प्रकाश कर सकता है; घृणा घृणा को नहीं मिटा सकती, यह काम केवल प्रेम कर सकता है।"

मार्टिन लूथर किंग जूनियर मानव इतिहास के उन विरले और युगद्रष्टा नेताओं में गिने जाते हैं, जिन्होंने नैतिक साहस, सत्य और अहिंसा की शक्ति से पूरे समाज की चेतना को झकझोर दिया। वे अमेरिका में नस्लीय भेदभाव और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का सबसे सशक्त प्रतीक बने। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि स्थायी परिवर्तन की सबसे प्रभावी राह हिंसा नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और धैर्य है। किंग का जन्म अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के अटलांटा शहर में हुआ। उनके पिता मार्टिन लूथर किंग सीनियर एक चर्च के पादरी थे। परिवार का धार्मिक और नैतिक वातावरण उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण रहा। बचपन से ही उन्होंने अन्याय और भेदभाव को निकट से देखा, जिसने उनके मन में सामाजिक समानता की गहरी चेतना पैदा की। शिक्षा के क्षेत्र में वे अत्यंत मेधावी थे। उन्होंने दर्शनशास्त्र में पीएचडी की और ईसाई धर्म के नैतिक मूल्यों को सामाजिक न्याय के विचार से जोडा। महात्मा गांधी की अहिंसक विचारधारा ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर को गहराई से प्रभावित किया। गांधी के सत्याग्रह से प्रेरणा लेकर किंग ने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन को अहिंसा का नैतिक आधार प्रदान किया। उनके लिए अहिंसा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अन्याय के सामने सबसे मजबूत प्रतिरोध थी। 1950 के दशक में अमेरिका में अश्वेत नागरिकों के साथ व्यापक भेदभाव व्याप्त था। बसों, स्कूलों, मतदान अधिकार और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में नस्लीय अलगाव खुलकर लागू था। 1955 में अश्वेत महिला रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के बाद मोंटगोमेरी बस बहिष्कार की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग ने किया और अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से इसे ऐतिहासिक सफलता दिलाई। यह आंदोलन अमेरिका में नागरिक अधिकार संघर्ष का निर्णायक मोड़ साबित हुआ और किंग राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। 1963 में वॉशिंगटन डीसी में दिया गया उनका प्रसिद्ध भाषण "आई हैव ए ड्रीम" विश्व इतिहास के सबसे प्रभावशाली भाषणों में से एक माना जाता है। इसमें उन्होंने एक ऐसे अमेरिका का स्वप्न प्रस्तुत किया, जहां मनुष्य की पहचान उसकी त्वचा के रंग से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कर्म से हो। यह भाषण केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में समानता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का प्रेरणास्रोत बन गया।हालांकि उनका संघर्ष आसान नहीं था। उन्हें बार-बार गिरफ्तार किया गया, जान से मारने की धमकियां मिलीं और निरंतर मानसिक दबाव झेलना पडा। अंततः 4 अप्रैल 1968 को टेनेसी के मेम्फिस शहर में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर का विचार और संदेश उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं हुआ। उनकी शहादत ने आंदोलन को और अधिक मजबूती प्रदान की।

जीवन ऊर्जा

गामाल अब्देल नासिर : जन्म 15 जनवरी 1918

जन्म

गामाल अब्देल नासिर (15 जनवरी 1918 – 28 सितंबर 1970) मिस्र के महान क्रांतिकारी नेता, सैनिक और अरब राष्ट्रवाद के प्रमुख स्तंभ थे। उनका जन्म मिस्र के अलेक्ज़ान्द्रिया में हुआ। 1952 की मिस्र क्रांति के बाद वे राष्ट्रीय मंच पर उभरे और 1956 में देश के राष्ट्रपति बने।

नेतृत्व वही है, जो जनता के दुःख को अपना समझे

साम्राज्यवाद और विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध सशक्त संघर्ष किया तथा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर विश्व राजनीति में साहसिक मिसाल पेश की। नासिर सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और अरब एकता के प्रबल समर्थक थे। 28 सितंबर 1970 को उनके निधन के साथ एक युग का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी अरब जगत और विकासशील देशों को प्रेरणा देते हैं। "जो राष्ट्र अपने सम्मान की रक्षा नहीं करता, वह इतिहास में जीवित नहीं रहता; स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं होती, इसे संघर्ष से प्राप्त किया जाता है; साम्राज्यवाद का विरोध केवल राजनीति नहीं, आत्मसम्मान का प्रश्न है; हम शांति चाहते हैं, लेकिन गुलामी की कीमत पर नहीं; एकजुट जनता को कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती; राष्ट्र की आत्मा उसकी जनता में बसती है, महलों में नहीं; सच्चा नेतृत्व वही है जो जनता के दुःख को अपना दुःख समझे; डर से नहीं, विश्वास से क्रांति जन्म लेती है; जो अपने संसाधनों पर अधिकार नहीं रखता, वह स्वतंत्र नहीं हो सकता; सम्मान के बिना जीवन केवल अस्तित्व है, गरिमा नहीं; विदेशी दबाव के आगे झुकना राष्ट्र के भविष्य को गिरवी रखना है; हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपमान स्वीकार भी नहीं करेंगे; जनता की शक्ति हथियारों से कहीं अधिक मजबूत होती है; राष्ट्र निर्माण भाषणों से नहीं, बलिदान से होता है; सामाजिक न्याय

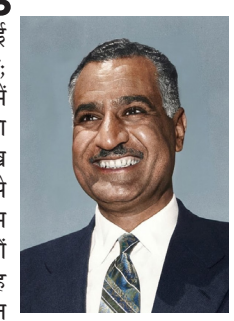

के बिना स्वतंत्रता अधूरी है; एक सशक्त राष्ट्र वही है जो आत्मनिर्भर हो; क्रांति का अर्थ विनाश नहीं, नव निर्माण है; जो देश अपनी जनता को भूखा रखता है, वह सुरक्षित नहीं रह सकता; राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए; सच्ची आजादी तभी है, जब किसान, मजदूर और गरीब सम्मान से जिएं; इतिहास कायरों को नहीं, साहसी लोगों को याद रखता है; शक्ति का सही उपयोग जनता के हित में होता है; विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष आत्मा की लड़ाई है; राष्ट्र की असली पूंजी उसकी जनता होती है; स्वाभिमान वह धन है, जिसे कोई छीन नहीं सकता।"

सर्वसिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ बिजाना शाजापुर मध्यप्रदेश

स्नान, शुद्धता और शास्त्र अध्ययन : एक व्यापक दृष्टि

पंडित कैलाशचंद्र शर्मा
वैदिक सनातन संस्कृति के प्रचारक व सर्व सिद्ध श्री बगलामुखी तारा महाशक्ति पीठ के संस्थापक।
मो. नं. 9425980556

यह प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठता है कि अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में, जहां प्रतिदिन स्नान करना या हर दिन धुले वस्त्र पहनना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता, वहां क्या बिना स्नान किए भागवत पुराण, श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषद या अन्य पवित्र ग्रंथों का अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही यह भी कि यदि केवल संग्रहित गोमूत्र या तीर्थ के पवित्र जल की कुछ बूंदें अपने ऊपर छिडक ली जाएं, तो क्या उसे शुद्धि माना जा सकता है। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि स्नान से मनुष्य पवित्र नहीं होता, केवल उसका शरीर शुद्ध होता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य स्वयं कभी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो सकता, चाहे वह गंगा तट पर ही क्यों न निवास करे। हम सब अपने साथ अनंत जन्मों के कर्मों—पाप और पुण्य—की गठरी लेकर चलते हैं। स्नान उस गठरी को नहीं धोता, परंतु शरीर और मन को संतुलित करता है। शरीर की शुद्धि आवश्यक इसलिए है क्योंकि वही स्वास्थ्य का आधार है। शुद्ध शरीर से ही शुद्ध विचार जन्म लेते हैं, हार्मोन का संतुलन ठीक रहता है और मानसिक स्थिरता आती है। अब यह समझना आवश्यक है कि स्नान और जल का इतना महत्व क्यों है। मनुष्य का जन्म जल से ही हुआ है। जब वह शुक्र के रूप में था, तब भी वह जलीय अंश में ही था। गर्भ में उसका पोषण जल के माध्यम से हुआ और उसी जल से उसके सभी अंग विकसित हुए। आज भी मानव शरीर का लगभग 70 प्रतिशत से अधिक भाग जल से बना है। जल ही जीवन है। नारायण नाम का अर्थ भी यही है—"नारि" अर्थात जल में निवास करने वाला। इसी से नर और नारी शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। हमारी नाभि में स्थित कुंडलिनी शक्ति का केंद्र, जिसे कमल कहा जाता है, उसका निवास भी जल तत्व से जुडा है। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति जल से ही हुई है और इसी कारण हमारे विचार, चेतना और भावनाएं जल से गहराई से प्रभावित होती हैं। विश्व की कोई भी सभ्यता उठाकर देख लीजिए—सभी नदियों, सरोवरों और जल स्रोतों के आसपास ही विकसित हुईं। बुद्धि, मेधा और प्रज्ञा का विकास जल के बिना संभव नहीं। यही कारण है कि हमारे सभी तीर्थ स्थल नदियों, सरोवरों या समुद्रों के तट पर स्थित हैं। ऋषि, मुनि, साधु और संतों ने भी सदैव जल स्रोतों के पास ही अपने आश्रम बनाए। व्यवहारिक जीवन में भी इसका अनुभव हर व्यक्ति करता है। जब हम अत्यंत अशांत, थके या दुखी होते हैं और केवल स्नान कर लेते हैं, तो भीतर एक नई चेतना और ऊर्जा का संचार होता है। अक्सर देखा गया है कि स्नान करते समय ही सबसे अधिक विचार आते हैं, गीत स्वतः फूट पडते हैं। अर्चिमिडीज को भी अपना महान सिद्धांत स्नानागार में ही सूझा था, जिसके कारण वह "यूरेका–यूरेका" कहते हुए बाहर निकल पडा। हमारे अधिकांश शास्त्रों और ग्रंथों की रचना भी जल के समीप ही हुई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना चित्रकूट के रामघाट और काशी के अस्सी घाट पर पूर्ण की।

अपने विचार

तेजस्वी देर से सोकर उठते हैं। उन्हें जयचंदों ने घेर रखा होगा। वह रात 9 बजे तक उनका इंतजार करेंगे। उनसे जाकर पूछिए, आने का मन है या नहीं। हमने तो न्योता दिया है। पिताजी (लालू) आए हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है। माता-पिता सबका आशीर्वाद है।

–तेज प्रताप
अध्यक्ष, जनशक्ति जनता दल

अगर आप आज वोटिंग मिस करते हैं, तो इसे पक्की हार समझिए। अगर यह शहर आज आपके हाथ से उनके हाथ में चला गया, तो कल आप किससे शिकायत करेंगे। आज मैं दूसरी पार्टियों के मराठी लोगों से अपील करता हूं। वह सब छोड़ो। मराठी लोगों के लिए एक हो जाओ। इस

–राज ठाकरे
अध्यक्ष, मनसे

आजादी के बाद कांग्रेस ने अपने शासन काल में धर्म के आधार पर नफरत की राजनीति पर जो लचकदार नीति अपनाई उसने देश और संविधान दोनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। आज जिस तरह संविधान और लोकतांत्रिक चरित्रों को खुले तौर पर

–मौलाना अरशद मदनी
जमीयत अध्यक्ष

विपक्ष की नेता आतिशी ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वे पिछले कई दिनों से सार्वजनिक जीवन से गायब हैं। यह अपने आप में दिखाता है कि उन्हें अपनी गलती का अहसास है और वे जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं।

–मनजिंदर सिंह सिरसा
मंत्री, दिल्ली सरकार

अपने विचार

डीबीडी कार्यालय

ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के.के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001

indiagroundreport@gmail.com

भेज सकते हैं।

यह अखबार "माध्यम कार्पोरेट सर्विसेज लि." के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक अरुण लाल द्वारा ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं. 2, के. के. चैम्बर्स, पुरुषोत्तमदास ठाकरदास रोड, फोर्ट, मुंबई- 400001 से प्रकाशित एवं सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन.के.इंडस्ट्रियल इस्टेट, इनसाइड प्रवासी इंडिस्ट्रयल इस्टेट गेट नं. 2, गोरेगांव पू., मुंबई-63 से मुद्रित. फोन नं. 022-66555719 ईमेल : indiagroundreport@gmail.com **कार्यकारी संपादक :** अमित बृज (पी.आर.बी. अधिनियम के अंतर्गत खबरों के चयन के लिए ज्मिेदार).

'हिंदुत्व हमारी आत्मा, वोट के लिए दिखावा नहीं'

निकाय चुनाव से पहले सीएम फडणवीस का विपक्ष पर हमला

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगामी निकाय चुनावों से पहले अपनी पार्टी की वैचारिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाजपा के लिए हिंदुत्व केवल एक चुनावी नारा नहीं, बल्कि उसकी ₹आत्मा₹ है। सीएम फडणवीस ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी ने कभी भी वोट हासिल करने के लिए हिंदुत्व का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उसकी पूजा की है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व मराठी समाज में गहराई से जुड़ा हुआ है और उनकी सरकार हर जाति व समुदाय की परंपराओं और रीति-रिवाजों का सम्मान करती है।

ओवैसी के 'हिजाब मेयर' बयान पर पलटवार

मुख्यमंत्री ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने गठबंधन सरकार बनने पर हिजाब पहनने वाली महिला के मेयर बनने की बात कही थी। फडणवीस ने इसे मराठी अस्मिता को भ्रमित करने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई 'मराठी मुसलमानों' के साथ गठबंधन की आड़ में इस तरह के दावे करता है और समाज को भ्रमित करने की कोशिश करता है, तब हिंदुत्व की वास्तविकता को जनता के सामने रखना अनिवार्य हो जाता है।

उद्धव ठाकरे पर तुष्टिकरण का आरोप

फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वे चुनावी फायदे के लिए हिंदुत्व से दूरी बना रहे हैं। सीएम ने कहा कि केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी मूल विचारधारा को छोड़ना और किसी विशेष समुदाय को लुभाने का प्रयास करना सही नहीं है।

बालासाहेब के सपने और लाउडस्पीकर विवाद

लाउडस्पीकर विवाद का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने बालासाहेब ठाकरे के उस लंबे समय से चले आ रहे सपने को पूरा किया है, जिसमें वे धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के पक्षधर थे। फडणवीस ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए की गई है। उन्होंने उन नेताओं को भी आड़े हाथों लिया जो सत्ता में वापसी पर लाउडस्पीकर दोबारा लगवाने का दावा कर रहे हैं, और कहा कि उन्हें अपने इस व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए।

वोटिंग के दिन आधी रात तक चलेगी मेट्रो एक्वा लाइन

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो-3 'एक्वा लाइन' ने 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए विशेष परिचालन योजना तैयार की है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधा के लिए मेट्रो प्रशासन ने गुरुवार को स्पेशल एक्स्ट्रा रन चलाने का निर्णय लिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कर्मचारी अपने आवंटित मतदान केंद्रों पर समय पर पहुँच सकें, मेट्रो सेवाएं सुबह 5:00 बजे से ही शुरू कर दी जाएंगी। यह कदम चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है, जिससे दूर-दराज से आने वाले कर्मचारियों को परिवहन की चिंता न रहे। सुबह की जल्दी शुरुआत के साथ-साथ, देर रात तक काम करने वाले चुनाव कर्मियों की वापसी के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दिन मेट्रो सेवा आधी रात 12:00 बजे तक जारी रहेगी। एक्वा लाइन, जो कोलाबा से आरे तक के महत्वपूर्ण व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ती है, इस दिन आम यात्रियों के साथ-साथ चुनाव अधिकारियों के लिए भी यात्रा को सुगम बनाएगी।

आरटी-पीसीआर नेगेटिव होने पर भी नहीं रुकेगा कोरोना मुआवजा

सिर्फ रिपोर्ट के आधार पर दावा खारिज करना गलत: बॉम्बे हाईकोर्ट

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान जान गंवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों (₹कोरोना वॉरियर्स₹) के परिवारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण और मानवीय फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट व्यवस्था दी है कि कोरोना से हुई मौत के मुआवजे को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि मृतक की आरटी-पीसीआर (RT-PCR) रिपोर्ट नेगेटिव थी। कोर्ट ने कहा कि यदि सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल रिकॉर्ड संक्रमण की पुष्टि करते हैं, तो तकनीकी आधार पर क्लेम को रोका नहीं जाना चाहिए। यह फैसला एक नर्स के मामले में आया है, जिसकी ड्यूटी के दौरान संक्रमण से मौत हो गई थी, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट के कारण उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिल पा रहा था।

बीमा राशि के लिए पति ने दी थी चुनौती

यह मामला माचिंद्र गायकवाड़ द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिनकी पत्नी 1993 से अहिल्यानगर सिविल अस्पताल में नर्स के रूप में कार्यरत थीं। मई 2021 में, कोरोना की दूसरी घातक लहर के दौरान ड्यूटी करते समय वे संक्रमित हुईं और उनकी मृत्यु हो गई। गायकवाड़ ने 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना' के तहत 50 लाख रुपये के बीमा मुआवजे के लिए आवेदन किया था।

मेडिकल सबूत और लक्षणों को माना अहम

न्यायमूर्ति अरुण पेडनेकर और न्यायमूर्ति वैषाली जाधव की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन के तर्क को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि कई मामलों में आरटी-पीसीआर रिपोर्ट 'फॉल्स नेगेटिव' (गलत) आ सकती है। कोर्ट ने पाया कि भले ही रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन मृतका का सीटी स्कैन, गिरता ऑक्सीजन लेवल और मृत्यु प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से यह साबित करते हैं कि मौत का कारण कोविड-19 ही था। अदालत ने यह भी संज्ञान लिया कि नर्स क्वारंटीन सेंटर में तैनात थीं और सीधे संक्रमित मरीजों की सेवा कर रही थीं, जिससे संक्रमण का खतरा सर्वाधिक था।

बॉम्बे हाईकोर्ट का अनूठा आदेश

ईडी के जमा पैसों के ब्याज से होगी बलिदानी के परिवारों की मदद

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोंसले की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया है कि अदालत में जमा कराए गए 46.5 करोड़ रुपये पर अर्जित ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा 'सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष' (Armed Forces Battle Casualties Welfare Fund) में जमा किया जाए। अदालत ने टिप्पणी की कि शहीदों के परिवारों और उनकी विधवाओं को तत्काल सहायता की आवश्यकता है और न्याय के हित में इस राशि का सदुपयोग किया जाना चाहिए।

जमीन सौदे और 'अपराध की कमाई' का विवाद

इस कानूनी लड़ाई की जड़ एसपीसीएल और नीलेश ठाकुर के बीच 2005 में हुआ एक जमीन सौदा था। कंपनी ने अलीबाग और पेन में 900 एकड़ जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था। ईडी का आरोप था कि नीलेश ठाकुर (एक सरकारी कर्मचारी) को दिए गए पैसे 'आय से अधिक संपत्ति' के मामले से जुड़े थे और इसे 'अपराध की कमाई' (Proceeds of Crime) करार दिया था। वहीं, कंपनी की दलील थी कि यह पैसा पूरी तरह वैध था और इसे जमीन खरीद के लिए 'एडवांस पेमेंट' के तौर पर दिया गया था, जिसका जिक्र इनकम टैक्स रिकॉर्ड में भी है।

ईडी की अपील खारिज, कंपनी को राशि लौटाने का निर्देश

यह मामला शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी लिमिटेड (एसपीसीएल) की संपत्ति कुर्की से जुड़ा था। ईडी ने 2019 के अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कंपनी की 141.50 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्की रद्द कर दी गई थी। उस समय हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगाते हुए ईडी को 46.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। अब अपने अंतिम फैसले में हाईकोर्ट ने ईडी की अपील खारिज कर दी है और ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मूल राशि (46.5 करोड़) कंपनी को वापस करने का आदेश दिया, लेकिन उस पर मिले ब्याज का आधा हिस्सा सेना के कल्याण कोष में देने को कहा।

सम्मान से संकल्प और दायित्व दोनों बढ़ते हैं : डॉ. हेमन्त कुमार तांतिया

GJEPC द्वारा रत्न-आभूषण उद्योग के दिग्गजों को 'हॉल ऑफ फेम' सम्मान

डॉ. हेमन्त कुमार तांतिया को 'Sparkling Future' पुस्तक एवं गहन शोध के लिए विशेष सम्मान

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन प्रतिष्ठित संस्था रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (GJEPC) द्वारा आयोजित चार दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो (IIJS) के दौरान एक भव्य एवं गरिमामय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश-विदेश के रत्न एवं आभूषण उद्योग से जुड़े अनेक प्रतिष्ठित उद्योगपतियों और विशेषज्ञों को उनके असाधारण योगदान के लिए 'हॉल ऑफ फेम' सम्मान से अलंकृत किया गया।

सम्मानित हस्तियों में विशिनदास होलाराम के निदेशक श्री दिलीप कुमार लाखी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के श्री सचिन जैन, चेन एन चेन्स (CNC) के डायरेक्टर श्री वसंतराज बिरावत सहित उद्योग जगत के अनेक विख्यात नाम शामिल रहे। इसी समारोह में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र में गहन अनुसंधान तथा इस क्षेत्र में भारत की निर्यात क्षमता पर आधारित चर्चित पुस्तक "Sparkling Future" की रचना के लिए डॉ. हेमन्त कुमार तांतिया को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यह सम्मान ज्ञान-सृजन और बौद्धिक योगदान को समर्पित एक महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में देखा गया।

'यह सम्मान मंजिल नहीं, नए दायित्वों का आरंभ'

वर्तमान में डॉ. तांतिया भारत सरकार के सीमा शुल्क एवं केंद्रीय जीएसटी विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा इस रणनीतिक उद्योग पर शोधपरक पुस्तक लेखन और नीति-उन्मुख विश्लेषण प्रस्तुत किया जाना उद्योग जगत द्वारा अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायक माना गया। सम्मान प्राप्त करने के बाद अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हुए डॉ. तांतिया ने कहा कि वर्ष 2026 की शुरुआत में GJEPC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से मिला यह सम्मान उनके लिए नई ऊर्जा, उत्तरदायित्व और प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, "यह सम्मान मुझे भारतीय अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए और अधिक समर्पण, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है।" उन्होंने GJEPC और उसके अध्यक्ष श्री किरीट भंसाली के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा, "यह सम्मान कोई मंज़िल नहीं, बल्कि बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ एक नई और अधिक सार्थक यात्रा की शुरुआत है।"

छठी लाइन के निर्माण कार्य के लिए मेजर ब्लॉक

मुंबई। पश्चिम रेलवे द्वारा कांदिवली और बोरीवली सेक्शन के बीच छठी लाइन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए 20/21 दिसंबर, 2025 की रात से 30 दिनों का ब्लॉक लिया जा रहा है, जो 18 जनवरी, 2026 तक जारी रहेगा। इस ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेन सेवाएं प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपर्युक्त कार्य के संबंध में 16/17 एवं 17/18 जनवरी, 2026 की रात्रि के दौरान बोरीवली और मालाड के बीच अप फास्ट लाइन पर रात 23:15 बजे से 03:15 बजे तक तथा डाउन फास्ट लाइन पर 01:00 बजे से 04:30 बजे तक मेजर ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे
विभिन्न NFR मीडिया कार्य

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे मंडल रेल प्रबंधक, वाणिज्य विभाग, NFR अनुभाग,मुंबई सेंट्रल, मुंबई – 400 008 **कार्य: मुंबई मंडल में विभिन्न NFR मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शन। नीलामी कैटलॉग संख्या: MMCT-PnU-25-15 नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट) : 02-02-2026 को 13:00:00 बजे लॉट संख्या : PnU-BCT-ST-WRL-44-26-1** (पे एंड यूज लाउंज / प्रतीक्षालय / रिटायरिंग रूम / क्लोक रूम) स्थान / क्षेत्र: मुंबई मंडल के सूरत (ST) स्टेशन पर क्लोक रूम सेवाओं का नवीनीकरण, प्रबंधन, अनुरक्षण, संचालन एवं मैनिंग 05 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए। **अवधि (दिन):** 1826 **ई-नीलामी की समापन तिथि एवं समय:** 02-02-2026 को 13:30:00 बजे **संपर्क विवरण: लैंडलाइन नंबर:** 022-67644212 ई-मेल आईडी: acmadvtgbct@gmail.com **नोट:** भावी बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट **(www.ireps.gov.in)** पर उपलब्ध ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल देखें। लॉट-वार विवरण उपरोक्त कैटलॉग में उपलब्ध है।

1004

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

नोटीस

सदर प्रकट करण्यात येत आहे की, मी **श्री नरेश बक्तावर बहनवाल**, रहिवासी श्री सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, बिल्डिंग क्र. ३/बी, तळ मजला सदनिका क्र. ००४, क्षेत्र ६६० चौ. फूट ही प्रॉपर्टी **मे. रॉयल इंटरप्रायझेस** तर्फे **श्री दिलीप विजयदत्त मिश्रा व श्री राजीव भूपनारायण मिश्रा** यांचा कुलमुखत्यार म्हणून **श्री दिलीप प्रभाकर पाटील** यांच्याकडून दिनांक २७/०३/२०१७ रोजी रजिस्टर्ड दस्त क्र. १७६५/२०१७ अन्वये खरेदी केलेली आहे.

सदर दस्त दिनांक १०/०१/२०२६ रोजी नारपोली पोलीस स्टेशन हद्दीत गहाळ झालेले असल्याने, सर्वसामान्यांना सूचित केले जाते की, या दस्ताबद्दल कोणत्याही व्यवहारासाठी मीच अधिकृत व्यक्ती आहे. सदर नोटीस गहाळ दस्ताबद्दल जनजागृतीसाठी प्रकाशित करण्यात येत आहे.

पत्ता- श्री सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, बिल्डिंग क्र ३/बी.तळ मजला, सदनिका क्र ००४, कशेळी ता. भिवंडी, जि. ठाणे.

संपर्क/-
श्री नरेश बक्तावर बहनवाल
फोन: ८०८०८०८९५१

भिवंडी पावरलूम को- ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड., भिवंडी
रजिस्टर्ड ऑफिस: 3, बंगालपूरा, भिवंडी जि. ठाणे 421302

नोटीस

भिवंडी पावरलूम को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, भिवंडी की 25वीं वार्षिक (ANNUAL) जनरल मीटिंग बुधवार तारीख - 28/01/2025 ठीक 11:00 सिल्को हाउस, गोकुल नगर, चाचा नेहरू हिंदी हाई स्कूल के सामने भिवंडी, नीचे दिए गए एजेंडे तय करने के लिए बुलाई गई है।

सभी शेयर होल्डर से गुजारिश है कि इस मीटिंग में वक्त पर आएं और मीटिंग को कामयाब बनाएं।

मिटींग का एजेंडा

1. तारीख 17/09/2023 की पिछली वार्षिक मीटिंग का मिनिट्स पढ़कर उसे कायम करना और मंजूरी देना
2. सन 2023-24 साल का वार्षिक अहवाल और हिसाब किताब, नफा - तोटा पत्रक पढ़कर उसे कायम करना व मंजूरी देना।
3. सन 2024-25, 2025-26 साल के लिए ऑडिटर (AUDITOR) कायम करना।
4. सन 2020-21 2021-22 के देय (PAYBLE) डिविडेंड को राइट ऑफ (WRITE OFF) करके रिजर्व फंड (RESERVE FUND) में ट्रांसफर करने के विषय को मंजूरी देना।
5. भिवंडी पावरलूम कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के सावंदे और भीनार की जमीन के सिलसिले में जो शासकीय शुल्क कलेक्टर ऑफिस में भरना है उसके बारे में मंजूरी देना।
6. माननीय प्रशासक साहब के इजाजत से दिगर एजेंट पर चर्चा करना।

तारीख : 15/01/2026
स्थान: भिवंडी

श्री लक्ष्मण विट्ठल भेरे
प्रशासक
भिवंडी पावरलूम को ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

राहत | मुंबई हार्बर लाइन पर 26 जनवरी से फिर दौड़ेंगी एसी लोकल

सीएसएमटी से पनवेल के बीच कूल-कूल होगा सफर

मुंबई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल सेवा में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक बड़ा और सुखद बदलाव होने जा रहा है। मध्य रेलवे (CR) ने यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकारते हुए हार्बर लाइन पर 26 जनवरी, 2026 से 14 वातानुकूलित (एसी) सेवाएं पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। नवी मुंबई की ओर बढ़ते कॉर्पोरेट वर्कफोर्स और मुंबई की उमस भरी गर्मी में आरामदायक सफर की आवश्यकता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह निर्णय उन लाखों दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो सीएसएमटी से पनवेल के बीच सफर करते हैं।

> हार्बर रूट पर यात्रियों की भारी मांग और नवी मुंबई की ओर बढ़ते कॉर्पोरेट मूवमेंट को देखते हुए हमने 14 एसी सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। यह कदम यात्रियों के सफर को सुखद और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
> – **स्वप्निल निला,** मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ), मध्य रेलवे

छुट्टियों पर सामान्य सेवा, पीक आवर्स पर जोर

नई समय सारिणी के अनुसार, हार्बर लाइन पर कुल सेवाओं की संख्या (614) में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, बल्कि 14 सामान्य लोकल ट्रेनों को एसी ट्रेनों से बदल दिया जाएगा। इसमें 7 'अप' और 7 'डाउन' सेवाएं शामिल होंगी। रेलवे ने विशेष रूप से कार्यालय जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 'पीक आवर्स' पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें सुबह 1 और शाम को 2 एसी सेवाएं दी जाएंगी। दिन की पहली एसी सेवा सुबह 4:15 बजे वाशी से वडाला के लिए रवाना होगी। हालांकि, रविवार और सार्वजनिक छुट्टियों के दिन एसी सेवाएं नहीं चलेंगी और उनकी जगह सामान्य ट्रेनें ही संचालित होंगी।

करीब 1.5 लाख प्रथम श्रेणी के यात्री करते हैं सफर

हार्बर लाइन पर रोजाना लगभग 10 से 12 लाख यात्री सफर करते हैं, जिनमें से करीब 1.5 लाख यात्री प्रथम श्रेणी के हैं। मध्य रेलवे की मुख्य लाइन (Main Line) पर एसी यात्रियों की संख्या में हालिया 30% की वृद्धि को देखते हुए हार्बर रूट पर इसे दोबारा उतारने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में कम रिस्पॉन्स के कारण इस रूट पर एसी ट्रेनें बंद कर दी गई थीं, लेकिन इस बार रेलवे ने पिछली गलतियों से सीखते हुए समय सारिणी में रणनीतिक बदलाव किए हैं!

मध्य रेल
सोलापुर मंडल
सिग्नलिंग कार्य

निविदा सूचना संख्या सोला-एन-टी-2025-26-37. Date:-13.01.2026 भारत के राष्ट्रपति की ओर से डीआरएम (एस एंड टी) कार्यालय, मध्य रेलवे, सोलापुर निम्नलिखित कार्यों के लिए सक्षम, प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से रेलवे की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है: **इलाके के साथ काम का नाम:** मध्य रेलवे के सोलापुर डिवीजन में पुलों के पुनर्निर्माण और विस्तार से संबंधित सिग्नलिंग कार्य, कमजोर पुलों और सुरंगों को मजबूत करना। **कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 1,27,23,245.45/-. **टेंडर फॉर्म की कीमत :** शुन्य. **जमा की जाने वाली धरोहर राशि:** ₹ 2,13,600/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 12 महीने. **निविदा के समापन की तिथि और समय: 04.02.2026** after **15.30 hrs.** विवरण **ireps** वेबसाइट में उपलब्ध हैं। शुद्धिपत्र/संशोधन यदि कोई हो तो केवल उपरोक्त ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। केवल ऑनलाइन निविदाएं ही स्वीकार की जाएंगी। मैनुअल/डाक/ई-मेल, फैक्स, हस्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे कंपनी के नाम के साथ तृतीय श्रेणी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त करें और इसे **www.ireps.gov.in** पर पंजीकृत करें। बयाना राशि (ईएमडी) का भुगतान नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे के माध्यम से या बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जाएगा और मूल बैंक गारंटी निविदा दस्तावेज़ में निर्दिष्ट नामित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि से पहले (अर्थात बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि को छोड़कर) जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया **www.ireps.gov.in** देखें।

मं.रे.प्र. - एस एंड टी शाखा
मध्य रेल, सोलापुर

Akar/Sur-6

अनाधिकृत रूप से रेल लाइन को पार करना दंडनीय अपराध है

पश्चिम रेलवे
मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य

मंडलीय रेल प्रबंधक (WA), पश्चिम रेलवे, 6वीं मंजिल, इंजीनियरिंग विभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई – 400008 द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु **ई-टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं: ई-टेंडर सूचना संख्या: BCT/25-26/294 दिनांक: 12.01.2026 कार्य का नाम एवं स्थान:** बांद्रा स्टेशन पर स्थित ग्रेड-I हेरिटेज (विरासत) संरचना की मरम्मत एवं अनुरक्षण कार्य। कार्य की अनुमानित लागत: 87,08,574.65/- **जमानत राशि (EMD):** 1,74,200/- **टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:** 06.02.2026 को 15:00 बजे तक **टेंडर खोलने की तिथि एवं समय:** 06.02.2026 को 15:30 बजे अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें: **www.ireps.gov.in**

0997

Like us on: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक,मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे मंडल रेल प्रबंधक, वाणिज्य विभाग, एनएफआर अनुभाग, मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008

कार्य का नाम: मुंबई मंडल में विभिन्न एनएफआर (Non-Fare Revenue) माध्यमों के माध्यम से विज्ञापन का प्रदर्शन।

नीलामी कैटलॉग संख्या	ई-नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट्स)
MMCTADVTMB25-10	30-01-26 को समय: 14:00 बजे

क्र. सं.	लॉट नंबर	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि और समय
1	MMS-MobGen-133732-2-26-1 (Misc-Mobile-Services General)	ट्रेन संख्या 12009/12010 शताब्दी एक्सप्रेस (मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल) में निःशुल्क लाइफस्टाइल पत्रिका के ऑनबोर्ड वितरण हेतु मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट। क्षेत्राधिकार: मुंबई डिवीजन, पश्चिम रेलवे।	1096	30-01-26 को 14:30 बजे

नीलामी कैटलॉग संख्या	ई-नीलामी प्रारंभ (सभी लॉट्स)
MMCT-ADVT-25-71	30-01-2026 को 15:00:00 बजे

क्र. सं.	लॉट नंबर	स्थान/क्षेत्र	दिन	ई-नीलामी की समाप्ति तिथि और समय
1	ADVT-BCT-DDR-OSN-443-25-1 (विज्ञापन – स्टेशन परिसर गैर-डिजिटल)	दादर (DDR) स्टेशन – फुट ओवर ब्रिज (FOB) दादर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिजों पर बल्क विज्ञापन अधिकार 3 वर्ष के लिए	1096	30-01-2026 को 15:30:00 बजे
2	ADVT-BCT-CYR-OSN-442-25-1 (विज्ञापन – स्टेशन परिसर (गैर-डिजिटल)	चर्नीरोड (CYR) स्टेशन कार्य: चर्नी रोड स्टेशन पर बल्क विज्ञापन अधिकार 3 वर्ष के लिए	1096	30-01-2026 को 15:40:00 बजे
3	ADVT-BCT-BA-OSN-440-25-1 (विज्ञापन – स्टेशन परिसर (गैर-डिजिटल)	बांद्रा (BA) स्टेशन – फुट ओवर ब्रिज (FOB) बांद्रा स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिजों पर बल्क विज्ञापन अधिकार 3 वर्ष के लिए	1096	30-01-2026 को 15:50:00 बजे
4	ADVT-BCT-DDR-OSN-339-25-1 (विज्ञापन – स्टेशन परिसर (गैर-डिजिटल)	दादर (DDR) स्टेशन – प्लेटफॉर्म कार्य: दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बल्क विज्ञापन अधिकार 3 वर्ष के लिए	1096	30-01-2026 को 16:00:00 बजे

संपर्क विवरण:लैंडलाइन नंबर: 022-6764 4212 ई-मेल आईडी: acmadvtgbct@gmail.com

सूचना: इच्छुक बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे IREPS वेबसाइट (www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध ई-नीलामी लीजिंग मॉड्यूल देखें। लॉट-वार (प्रत्येक लॉट का) विवरण वहाँ उल्लिखित कैटलॉग के अंतर्गत उपलब्ध है।

0998

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फालो करें: twitter.com/WesternRly

न्यूज ब्रीफ

संभल के बिछौली गांव में चला बुलडोजर

संभव। जनपद की सदर तहसील के ग्राम बिछौली में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम ने सीमांकन के बाद अतिक्रमण हटाया। पशुचर, स्कूल, पंचायत भवन, खेल मैदान व अन्य सार्वजनिक उपयोग की करीब 20 बीघा जमीन पर बने अवैध आवासीय व धार्मिक कब्जे हटाए गए। संबंधित मामलों में न्यायालय से पहले ही बेदखली के आदेश जारी हो चुके थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी अभियान जारी रहेगा।

जौनपुर में चाइनीज मांझे से डॉक्टर की गर्दन कटी

जौनपुर। जौनपुर जनपद के लाइन बाजार थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर चाइनीज मांझे की चपेट में आने से एक युवा डॉक्टर की मौत हो गई। हादसा पचहटिया स्थित प्रसाद तिराहे के पास उस समय हुआ, जब वह बाइक से घर लौट रहे थे। मृतक की पहचान केराकत तहसील क्षेत्र के शेखजादा मोहल्ला निवासी डॉ. समीर हाशमी (25) के रूप में हुई है। वह किसी कार्य से जौनपुर आए थे और काम निपटाकर दोपहर में वापस लौट रहे थे। हेलमेट पहने होने के बावजूद अचानक चाइनीज मांझा गले में फंस गया, जिससे उनकी गर्दन कट गई। हादसे के बाद वह सड़क पर गिर पड़े और अधिक खून बहने से अचेत हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता ने बताया कि चाइनीज मांझे के खिलाफ अभियान जारी है। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

ब्रेक फेल होने से चालक और खलासी की मौत

रायबरेली। रायबरेली जिले के गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। देदौर गांव के पास तेज रफ्तार लोडर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बनी पक्की दीवार से जा टकराया। हादसे में लोडर चालक और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोडर रायबरेली की ओर जा रहा था। सामने से आ रहे ट्रक को बचाने के दौरान चालक ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक फेल हो गया। इसी बीच वाहन का एक टायर निकल जाने से संतुलन बिगड़ गया और लोडर सीधे दीवार से जा भिड़ा। टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहन के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से गैस कटर से वाहन काटकर दोनों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल भेजा, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान सौरभ (21) और बृजेश (24) के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

अंधेरगर्दी: 27 मृतकों को भी मिला पीएम आवास

डीबीडी संवाददाता | बलिया

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन में बलिया जनपद से गंभीर लापरवाही और अनियमितता का मामला सामने आया है। वर्ष 2016 से 2024 के बीच जहां 250 अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दे दिया गया, वहीं 27 मृतक भी कागजों में आवास के लाभार्थी बन गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी के सख्त आदेश जारी किए हैं।

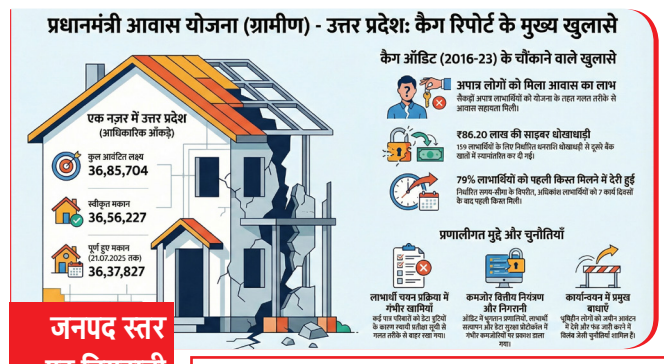

जनपद स्तर पर निगरानी और पारदर्शिता

डीएम ने लाभार्थियों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मनरेगा मजदूरी और आवास प्लस सर्वे पर भी ध्यान दिया। प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रधान की मौजूदगी में खुली बैठक कर पात्र और अपात्र व्यक्तियों की सूची ग्रामीणों के सामने पढ़ने का निर्देश दिया गया।

623 आवासों का लक्ष्य, कई अधूरे

जनपद में कुल 623 प्रधानमंत्री आवासों का लक्ष्य निर्धारित था, लेकिन गड़वार में 62, सोहांव में 8, रेवती में 8 और चिलकहर में 4 आवास अब तक पूर्ण नहीं हो सके हैं। जिलाधिकारी ने सभी लंबित आवासों के शीघ्र निर्माण और निस्तारण के निर्देश संबंधित विकासखंड अधिकारियों को दिए हैं। समीक्षा में यह भी सामने आया कि 80 आवास जमीनी विवाद में फंसे हैं और 31 आवास न्यायालय में लंबित हैं।

250 अपात्रों को लाभ, जांच में खुलासा

बलिया। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जिले में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। वर्ष 2016 से 2024 के बीच 250 अपात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दे दिया गया, वहीं 27 मृतक भी कागजों में आवास के लाभार्थी बने पाए गए। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी के आदेश जारी किए हैं।

जिम्मेदार अधिकारियों से होगी रिकवरी

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर से अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिला और मृतक नाम पर आवास स्वीकृत हुए, उनके वेतन से राशि की वसूली की जाएगी। इसके साथ ही सभी 623 आवासों का पुनः सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति न हो।

योजना की पात्रता और उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है या जो कच्चे व जर्जर मकानों में रह रहे हैं। पात्रता SECC और आवास प्लस सर्वे पर आधारित है। बेघर, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग सदस्य वाले, विधवा या अकेली महिला मुखिया वाले परिवार लाभार्थी माने जाते हैं। वहीं, चार पहिया वाहन, पक्का मकान, सरकारी नौकरी या अधिक संपत्ति वाले परिवार अपात्र माने जाते हैं। योजना का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों को पारदर्शी तरीके से आवास उपलब्ध कराना है।

संभल हिंसा: CO अनुज चौधरी कोतवाली प्रभारी नामजद

डीबीडी संवाददाता | संभल

संभल जनपद में शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में न्यायालय के आदेश ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। चंदौसी स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी (सीओ) संभल अनुज चौधरी और तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

सात दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कमर हुसैन के अनुसार, न्यायालय ने संबंधित थाने को न केवल मुकदमा दर्ज करने बल्कि सात दिन के भीतर इसकी सूचना अदालत को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद संभल हिंसा प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस की भूमिका पर अब न्यायिक जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना जताई जा रही है, वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को लेकर हलचल बढ़ गई है।

24 नवंबर 2024 की हिंसा से जुड़ा मामला

यह आदेश 24 नवंबर 2024 को सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित शाही जामा मस्जिद के दूसरे सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में घायल हुए युवक के मामले से संबंधित है। घटना के दौरान एक युवक को गोली लगने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा।

घायल युवक के पिता की याचिका पर सुनवाई

घायल युवक आलम के पिता यामीन ने न्यायालय में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि उनका बेटा सामान बेचने के लिए गया था, उसी दौरान उसे गोली मार दी गई। याचिका में तत्कालीन सीओ, इंस्पेक्टर सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मियों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई थी।

मुरादाबाद के रास्ते हावड़ा से दिल्ली जाएगी नई अमृत भारत स्पेशल

18 जनवरी को संतरागाछी जंक्शन पर किया जाएगा उद्घाटन

डीबीडी संवाददाता | मुरादाबाद

रेल यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक यात्रा विकल्प उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रेलवे ने हावड़ा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई अमृत भारत स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन मुरादाबाद जंक्शन होकर संचालित की जाएगी। ट्रेन का उद्घाटन 18 जनवरी को संतरागाछी जंक्शन से किया जाएगा। उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि ट्रेन संख्या 03065 संतरागाछी–आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत स्पेशल 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे संतरागाछी जंक्शन से रवाना होगी और अगले दिन रात्रि 9 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी।

3.50 बजे मुरादाबाद पहुंचेगी अमृत भारत

उन्होंने बताया कि यह ट्रेन 19 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 50 मिनट पर मुरादाबाद जंक्शन पहुंचेगी, जहां पांच मिनट का ठहराव होगा। इसके बाद ट्रेन 3 बजकर 55 मिनट पर मुरादाबाद से आनंद विहार टर्मिनल के लिए रवाना होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस नई सेवा से पूर्वी भारत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा और मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाले यात्रियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी साबित होगी।

12 घंटे बाद तालाब में मिला चार मासूमों का शव, फटा कलेजा

मृतकों में दो सगे भाई, पूरामुफ्ती के हुसैनपुर गांव में पसरा मातम

प्रयागराज। प्रयागराज जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अहमदपुर पावन गंगा गांव में मंगलवार से लापता चार बच्चों के शव उनके घर से करीब एक किलोमीटर दूर एक तालाब में मिलने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। एक ही परिवार के दो सगे भाइयों समेत चार मासूमों की असामयिक मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने जिला प्रशासन को मामले की गंभीरता से जांच कराने और सभी तथ्यों की गहराई से पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन की ओर से परिजनों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

मंगलवार शाम से थे लापता

मृत बच्चों की पहचान हुसैनपुर पावन गांव निवासी प्रदीप सोनकर के पुत्र प्रतीक सोनकर (12) और प्रिंस सोनकर (10), पड़ोसी प्रियांशु सोनकर (11) पुत्र स्वर्गीय संदीप सोनकर तथा राजेश सोनकर के पुत्र करन सोनकर (19) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, चारों बच्चे मंगलवार शाम करीब चार बजे घर से बाहर निकले थे और उसके बाद वापस नहीं लौटे। काफी तलाश के बावजूद बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को ग्रामीणों ने गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक तालाब में चारों के शव उतराते देखे, जिसके बाद सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से शवों को तालाब से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। घटनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण जुट गए थे और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

भर्ती परीक्षाओं में धांधली ED ने दाखिल की चार्जशीट

सिपाही और आरओ-एआरओ पेपर लीक मामले में 17 आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट

डीबीडी संवाददाता | लखनऊ

उत्तर प्रदेश की दो बड़ी भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी ने सिपाही भर्ती परीक्षा-2023 और यूपीपीएससी की आरओ व एआरओ भर्ती परीक्षा-2023 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपित समेत 17 लोगों के खिलाफ विशेष न्यायालय, लखनऊ में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है।

मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज है मामला

ईडी की ओर से यह पूरक चार्जशीट धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दाखिल की गई है। जांच में सामने आया है कि पेपर लीक के जरिए संगठित गिरोह ने अभ्यर्थियों से भारी रकम वसूल कर अवैध कमाई की। 18 और 19 फरवरी 2023 को प्रदेश भर में 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा से जुड़ी एक निजी कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने सीलबंद बक्सों को खोलकर प्रश्नपत्रों के उत्तर उपलब्ध कराए।

आरओ-एआरओ परीक्षा में भी अनियमितता

इसी तरह, यूपीपीएससी की आरओ व एआरओ भर्ती परीक्षा-2023 में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के साक्ष्य मिले थे। प्रारंभिक जांच के बाद दोनों मामलों की जांच एसटीएफ को सौंपी गई थी, जिसके बाद ईडी ने आर्थिक अपराध के पहलुओं की अलग से जांच शुरू की। ईडी के अनुसार, दोनों भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक और उससे अर्जित अवैध धन की परतें लगातार खोली जा रही हैं। पूरक आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और तेज होने की संभावना है।

व्यापार जगत

निर्यात तैयारी सूचकांक में महाराष्ट्र शीर्ष पर

नीति आयोग ने जारी किया आंकड़ा, तमिलनाडु दूसरे और गुजरात तीसरे पायदान पर

डीबीडी संवाददाता | नई दिल्ली

नीति आयोग ने बुधवार को निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2024 जारी किया। चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि तमिलनाडु और गुजरात क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। चौथे पर यूपी, पांचवें पर आंध्रप्रदेश, छठें पर कर्नाटक, सातवें पर पंजाब है। यह सूचकांक भारत के 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर के माल निर्यात लक्ष्य और विकसित भारत @2047 विजन के अनुरूप तैयार किया गया है। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा, इसके बाद क्रमशः जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव, गोवा तथा त्रिपुरा का स्थान है। सूचकांक भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारी और क्षमता का व्यापक मूल्यांकन करता है।

मुक्त व्यापार और आर्थिक साझेदारी का विस्तार

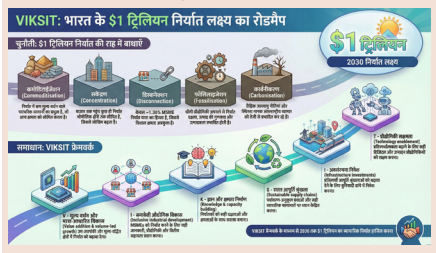

नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौतों का विस्तार हो रहा है, लेकिन मजबूत घरेलू आधार की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, "राज्यों को ऐसे परिवेश का निर्माण करना होगा जो नए अवसरों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सके, वैश्विक मानकों के अनुरूप हो और जिलों में प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए।" सुब्रह्मण्यम ने यह भी बताया कि हाल के वर्षों में कई राज्यों ने समर्पित नीतियों, संस्थानों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से अपनी निर्यात दृष्टि को मजबूत करना शुरू किया है। नीति आयोग के अनुसार, यह सूचकांक राज्यों और जिलों को प्रतिस्पर्धी निर्यात वातावरण तैयार करने और वैश्विक बाजार में मजबूत पकड़ बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

निर्यात तैयारी सूचकांक की पद्धति

- आंकड़ा-आधारित मूल्यांकन: निर्यात नीतियों, कारोबारी माहौल, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और निर्यात परिणामों सहित कई कारकों का आंकलन।
- समावेशी और प्रमाण-आधारित ढांचा: राज्यों और जिलों के निर्यात तंत्र की मजबूती, स्थिरता और समावेशिता का मूल्यांकन।
- नीतिगत सुधार और अवसर: सूचकांक के माध्यम से संरचनात्मक चुनौतियों, विकास अवसरों और आवश्यक नीतिगत उपायों की पहचान।
- डेटा स्रोत: आंकड़े राज्य और केंद्र सरकार दोनों के स्रोतों से जुटाए जाते हैं और प्रत्येक संकेतक को उसके महत्व के आधार पर भार दिया जाता है।

भारत के 33 करोड़ घरों में LPG कनेक्शन

स्वच्छ खाना पकाने में व्यापक बदलाव

डीबीडी संवाददाता | नई दिल्ली

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत में स्वच्छ खाना पकाने की पहलों के प्रभाव और एलपीजी के नियमित उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल कनेक्शन देना ही सफलता नहीं है, बल्कि इसका नियमित उपयोग असली सफलता की पहचान है। पुरी ने बताया कि वर्तमान में भारत में 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन संचालित हैं। यह नेटवर्क पूरे देश में एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है और साफ-सुथरे खाना पकाने के लिए नागरिकों तक सीधे लाभ पहुंचाता है।

एलपीजी रिफिल वितरण में वृद्धि

पुरी ने बताया कि अब तक लगभग 276 करोड़ रिफिल वितरित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में औसतन 13.6 लाख रिफिल प्रतिदिन वितरित किए जा रहे हैं, जबकि पूरे देश में प्रतिदिन 55 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं।

नियमित उपयोग में वास्तविक बदलाव

मंत्री ने कहा कि औसत खपत प्रति परिवार 3 सिलेंडर से बढ़कर 4.85 सिलेंडर हो गई है। यह बदलाव योजना की असली सफलता दर्शाता है। पुरी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ खाना पकाने की पहल का एक बड़ा और स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बताया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत अब तक 10.41 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।
- योजना के लक्ष्य के तहत अब 10.60 करोड़ कनेक्शन के करीब पहुंचा जा रहा है।
- रिफिल डेटा से स्पष्ट हुआ कि उपभोक्ताओं का व्यवहार बदल रहा है और एलपीजी का नियमित इस्तेमाल बढ़ा है।

चांदी ने तोड़ा रिकार्ड, कीमत 2.97 लाख प्रति किलो

डीबीडी संवाददाता | नई दिल्ली

घरेलू सर्राफा बाजार में हाजिर चांदी की कीमत लगातार तेजी के नए शिखर पर पहुंच गई है। देशभर में चांदी का भाव आज 2,74,900 रुपये से लेकर 2,97,900 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिक रहा है। दिल्ली में चांदी का मूल्य 2,75,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया, जबकि चेन्नई में यह सबसे अधिक 2,97,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही है।

वैश्विक और घरेलू बाजार में असर

मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों में चांदी की मांग सकारात्मक बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड और ईरान पर दिए गए संकेतों से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल उत्पन्न हो सकती है। साथ ही जनवरी के दूसरे पखवाड़े में औद्योगिक मांग में वृद्धि के कारण चांदी के भाव में तेजी जारी रहने की संभावना है। कैपेक्स गोल्ड एंड इनवेस्टमेंट्स के सीईओ राजीव दत्ता के अनुसार, इस साल घरेलू बाजार में चांदी की कीमत में अब तक 200 प्रतिशत से अधिक की तेजी आ चुकी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंदन सिल्वर मार्केट में हाजिर चांदी का मूल्य 90.95 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी और औद्योगिक क्षेत्र में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा, सुरक्षित निवेश (Safe Investment) के तौर पर भी चांदी में निवेश बढ़ा है, विशेषकर सिल्वर ईटीएफ में लगातार इनफ्लो देखा जा रहा है।

शहरों के बाजार में भाव का अंतर

देश के अलग-अलग हिस्सों की बात करें तो दिल्ली में 2,75,100 रुपये/किग्रा, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता में 2,74,900 रुपये/किग्रा, जयपुर, सूरत, पुणे में 2,75,200 रुपये/किग्रा, बेंगलुरु में 2,75,400 रुपये/किग्रा, पटना, भुवनेश्वर में 2,75,000 रुपये/किग्रा और हैदराबाद में 2,97,400 रुपये/किग्रा रहा। विशेष रूप से चेन्नई में चांदी ने नई ऊंचाई छुई, जहां यह 20,300 रुपये प्रति किलोग्राम की तेजी के साथ कारोबार कर रही है।

सुमाया समूह की 35.22 करोड़ की संपत्तियां जब्त

डीबीडी संवाददाता | नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुमाया समूह और उससे जुड़ी कंपनियों की लगभग 35.22 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई है। ईडी की यह कार्रवाई वर्ली पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। प्राथमिकी में आरोप है कि सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स ने अपनी 'नीड टू फीड' योजना के तहत निवेशकों को लाभ का झूठा वादा करके लगभग 137 करोड़ रुपये का गबन किया।

जब्त संपत्तियों का विवरण

ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने बताया कि जब्त संपत्तियों में बैंक बैलेंस, डीमैट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड जैसी चल संपत्तियां शामिल हैं, वहीं दो अचल संपत्तियां भी अटैच की गई हैं। इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है और जांच जारी है।

PMLA के तहत कार्रवाई

ईडी ने कहा कि इस जांच का मकसद धन शोधन की गतिविधियों को रोकना और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल संपत्तियों को जब्त करना है। एजेंसी का कहना है कि जब्त की गई संपत्तियां जांच प्रक्रिया और भविष्य के न्यायिक आदेशों तक सुरक्षित रखी जाएंगी।

रूस-ईरान समेत 75 देशों के लोगों की US में नो एंट्री

ट्रंप ने दिया एक और झटका, वीजा इश्यू पर रोक

एजेंसी । वाशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रूस-ईरान समेत कुल 75 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोकने का फैसला किया है। फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह रोक 21 जनवरी से लागू होगी। रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक आंतरिक मेमो का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के दूतावासों को निर्देश दिए गए हैं कि वे मौजूदा कानूनों के तहत वीज़ा जारी न करें, जब तक कि वीज़ा प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा पूरी न हो जाए। यानी अगले सप्ताह से शुरू होने वाला यह बैन अनिश्चितकाल के लिए लागू होने जा रहा है।

कौन-कौन से देश शामिल?

रिपोर्ट के अनुसार, सोमालिया, रूस, ईरान, अफ़ग़ानिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, थाईलैंड, मिस्र और यमन भी प्रभावित 75 देशों की उस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से इस रिपोर्ट पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह रोक कितने समय तक लागू रहेगी। यह फैसला ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा माना जा रहा है। जनवरी में पद संभालने के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने आव्रजन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं।

कोई समय सीमा नहीं बताई गई

विदेश विभाग के प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट किए गए मेमो पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, जिसके बारे में फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि यह अमेरिकी दूतावासों को मौजूदा कानून के तहत वीज़ा देने से इनकार करने का निर्देश देता है, जबकि विभाग अपनी प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है। कोई समय सीमा नहीं बताई गई।

ट्रंप ने पहले ही दिए थे संकेत

बता दें कि नवंबर में, ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास एक अफ़गान नागरिक द्वारा की गई गोलीबारी के बाद, जिसमें एक नेशनल गार्ड सदस्य मारा गया था, सभी रतीसरी दुनिया के देशोंर से आप्रवासन को रस्थायी रूप से रोकनेर का वादा किया था। फिलहाल यह साफ नहीं है कि वीज़ा प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होगी। माना जा रहा है कि अमेरिका अपनी सुरक्षा और आव्रजन प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद अगला फैसला लेगा।

लालू, तेजस्वी के खिलाफ मुकदमे पर रोक नहीं लगेगी : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह आईआरसीटीसी घोटाले में आरजेडी नेता लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक नहीं लगाएगा। हालांकि, अदालत ने कहा कि निचली अदालत अगले सप्ताह गवाहों से जिरह कर सकती है, तब तक वह मामले में आरोप तय करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पिता-पुत्र की याचिकाओं पर फैसला कर लेगी। लालू प्रसाद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि पिछली बार अदालत ने आरोप तय करने के खिलाफ दायर याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान मुकदमे पर रोक लगाने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। उन्होंने कहा कि गवाहों की जांच के बाद, ट्रायल कोर्ट गवाहों से जिरह की कार्यवाही शुरू करेगा। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि मुख्य जांच होने दीजिए। मैं उन्हें स्थगन आदेश नहीं दे रही हूं। उन्होंने आगे कहा कि वह स्थगन आदेश के मुद्दे पर पहले निर्णय लेने के बजाय अगले सप्ताह इस मामले का अंतिम फैसला करेंगी। याचिकाओं पर जल्द फैसला सुनाने का संकेत देते हुए, अदालत ने सीबीआई के वकील को अगले सप्ताह जिरह न करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगले सप्ताह जिरह शुरू करें और इस बीच मैं बहस पूरी करके फैसला सुना दूंगी।

आय से अधिक संपत्ति मामला

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायत खारिज

अमिताभ ठाकुर ने लगाए थे आरोप

एजेंसी । नई दिल्ली

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकपाल ने खारिज कर दी है। यह शिकायत एक्टिविस्ट अमिताभ ठाकुर ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दुबे और उनकी पत्नी के पास उनकी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति है। लोकपाल ने कहा कि शिकायत आधारहीन और तथ्यों से परे थी। संस्था ने यह भी माना कि यह मामला सांसद के बजाय उनकी पत्नी को कटघरे में खड़ा करने के इरादे से पेश किया गया था।

गोपनीयता का उल्लंघन और कार्रवाई की छूट

लोकपाल ने माना कि यह शिकायत संस्था की गोपनीयता बनाए रखने के नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करती है। ठाकुर को इसके लिए शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही, लोकपाल ने दुबे को यह अधिकार दिया कि वे इस मामले में ठाकुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। संस्था ने ठाकुर के रवैये की भी कड़ी आलोचना की।

हलफनामों के आधार पर लगाए गए आरोप

लोकपाल के 134 पेज के ऑर्डर में कहा गया कि ठाकुर ने दुबे पर आरोप उन तथ्यों के आधार पर लगाए थे, जिन्हें सांसद ने 2009 और 2024 के चुनावी हलफनामों में चुनाव आयोग के सामने पेश किया था। ठाकुर ने दुबे और उनकी पत्नी की आय में वृद्धि को लेकर आरोप लगाए, जबकि यह जानकारी खुद दुबे ने सार्वजनिक रूप से साझा की थी। इसके अलावा, ठाकुर ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस शिकायत की जानकारी लोगों तक पहुंचाई थी।

न्यूज़ ब्रीफ

पुलिस हिरासत में तीन पत्रकार

हैदराबाद। तेलंगाना की पुलिस ने एक महिला आईएएस अधिकारी के खिलाफ 'मानहानिकारक कंटेंट' के आरोप में तीन पत्रकारों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक एक तेलुगु टीवी न्यूज चैनल के तीन पत्रकारों को बुधवार (14 जनवरी) को महिला आईएएस अधिकारी के खिलाफ मानहानिकारक कंटेंट प्रसारित करने के आरोप में दर्ज मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। बीआरएस और भाजपा ने तेलंगाना में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए दावा किया कि तीनों पत्रकारों को 'गिरफ्तार' किया गया है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की है।

जस्टिस पॉल कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त

कोलकाता। जस्टिस सुजॉय पॉल को बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। वह अक्टूबर 2025 से उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 9 जनवरी को उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस पॉल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हैं। उन्हें मई 2011 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था और वह 62 साल की उम्र पूरी होने पर 20 जून 2026 को रिटायर होंगे।

सिंगर जुबीन की मौत डूबने से हुई : सिंगापुर पुलिस

सिंगापुर। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर सिंगापुर पुलिस ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया। पांच महीने बाद पुलिस ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके मुताबिक, जुबीन की मौत डूबने की वजह से हुई थी। उन्होंने नशे की हालत में लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। दरअसल 52 साल के सिंगर जुबीन की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में एक यॉट पार्टी के दौरान मौत हो गई थी। वे सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने पहुंचे थे। हालांकि परफॉर्मेंस से एक दिन पहले उनकी जान चली गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 25 नवंबर को विधानसभा में कहा था कि जुबीन गर्ग की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। वे दोषियों को सजा दिलाकर रहेंगे।

मानहानि मामले में केजरीवाल, संजय सिंह की याचिका खारिज

गांधीनगर। गुजरात हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं- अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में टिप्पणियां करने पर मानहानि के मामले में अलग-अलग सुनवाई की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट उनकी इस मांग को पहले ही खारिज कर चुका है। जस्टिस एमआर मेंगडे की एकल पीठ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों ने शहर की सत्र अदालतों की ओर से उनके आवेदन खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था।

ईडी की याचिका पर सुको में आज सुनवाई

सीएम ममता पर जांच में बाधा डालने का आरोप

एजेंसी । कोलकाता

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की आई-पैक कार्यालय पर छापेमारी के मामले ने राज्य के साथ-साथ देशभर की सियासत में गर्माहट तेज कर दी है। बयानबाजी और आरोप-प्रत्यारोप तेज हुआ तो यह मामला बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। ईडी की तरफ से दायर इस याचिका में पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने आई-पैक कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतिक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी में हस्तक्षेप किया और जांच में बाधा डाली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि छापेमारी के समय सीएम ममता बनर्जी खुद वहां आईं और फिर कथित तौर पर महत्वपूर्ण दस्तावेज के फाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गईं। एजेंसी का कहना है कि इससे अधिकारियों पर डर का माहौल बन गया और केंद्रीय जांच एजेंसी की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।

कलकत्ता हाईकोर्ट में भी दायर की थी याचिका

इससे पहले 9 जनवरी को ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की थी, जिसमें सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ईडी का दावा है कि ममता बनर्जी ने पुलिस की मदद से छापेमारी में एजेंसी की कब्जे में मौजूद संवेदनशील दस्तावेज अपने पास ले लिए।

अब समझिए क्या है पूरा मामला

बता दें कि यह पूरा मामला 8 जनवरी का है, जब ईडी ने कथित करोड़ों रुपये के कोल-पाइफरज स्कैम की जांच के तहत आई-पैक और प्रतिक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन किया। इस दौरान ममता बनर्जी आई-पैक कार्यालय पहुंचीं, ईडी अधिकारियों का सामना किया और कथित तौर पर दस्तावेज ले गईं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसी ने अतिक्रमण किया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि दूसरी ओर टीएमसी ने ईडी के बाधा डालने के आरोपों को खारिज किया। साथ ही कहा कि ईडी का आई-पैक पर कार्रवाई का असली मकसद पार्टी के चुनावी रणनीति दस्तावेज हासिल करना था, न कि किसी निष्पक्ष जांच को आगे बढ़ाना।

ट्रेन में नॉनवेज खाना परोसने पर रेलवे को नोटिस

एजेंसी । नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ट्रेन में परोसे जाने वाले नॉनवेज फूड को लेकर रेलवे बोर्ड और पर्यटन मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। NHRC ने सोमवार को लेटर जारी किया। जिसमें कहा गया कि ट्रेनों में परोसे जा रहे नॉनवेज फूड को लेकर रेलवे से मांगी गई रिपोर्ट अधूरी है। कई जरूरी जानकारी साफ नहीं की गई हैं। रेलवे बोर्ड से नई रिपोर्ट मांगी है। चार हफ्ते के भीतर जवाब देना होगा। दरअसल, सिख संगठनों की ओर से NHRC को शिकायत मिली थी कि ट्रेनों में मिलने वाले मांसाहारी खाने में केवल हलाल तरीके से तैयार मांस परोसा जाता है। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इससे यात्रियों के साथ भेदभाव होता है। इसी शिकायत के बाद NHRC ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया था।

17 जनवरी को इंदौर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी

भागीरथपुरा में मृत लोगों के परिजन से मिलेंगे

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी शनिवार को मध्यप्रदेश के इंदौर जाएंगे। इस दौरान वह भागीरथपुरा पहुंचकर दूषित पानी पीने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसी दिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगी।

अब तक 23 लोगों की मौत

भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे पर प्रदेश की सियासत भी गरमा चुकी है। कांग्रेस राज्य की मोहन यादव सरकार और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को घेर रही हैं। वहीं, कई वरिष्ठ भाजपा नेता भी इस मामले में अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस इंदौर में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।

भारत-ओमान समुद्री रिश्तों को नई मजबूती

आईएनएसवी कौण्डिन्य ने पूरी की 18 दिन की ऐतिहासिक यात्रा

अहमदाबाद। भारत और ओमान के बीच समुद्री रिश्तों को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक पल सामने आया है। इसके तहत भारतीय नौसेना के स्वदेशी पोत आईएनएसवी कौण्डिन्य ने गुजरात के पोर्बंदर से मस्कट ओमान तक 18 दिनों की साहसिक और ऐतिहासिक यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की। इस अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह जहाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह जहाज भारत की प्राचीन नौवहन कला और समुद्री परंपरा को विश्व के सामने पेश करता है। जहाज का नाम प्रसिद्ध नाविक कौण्डिन्य के नाम पर रखा गया है और इसे अजंता की गुफाओं में दिखाए गए 5वीं सदी के जहाज से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है।

आईएनएसवी कौण्डिन्य पर क्या बोले सोनोवाल

सोनोवाल ने बताया कि यह जहाज भारत की समुद्री विरासत और कौशल का प्रतीक है। इसे अजंता की गुफाओं में दिखाए गए 5वीं सदी के जहाज से प्रेरणा लेकर डिजाइन किया गया है और इसका नाम प्रसिद्ध नाविक कौण्डिन्य के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही मंत्री सोनोवाल ने भारत और ओमान के रिश्ते पर भी जोर दिया। मस्कट, ओमान से बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ओमान के समुद्री रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। हमारे पूर्वज जो इन जलमार्गों से गुजरते थे, वे आज भी दोनों देशों को जोड़ते हैं। सोनोवाल ने बताया कि हाल ही में भारत और ओमान के बीच सीईपीए, समुद्री विरासत पर सहमति पत्र और साझा दृष्टिकोण पर समझौते हुए हैं।

'अधजले नोट मामले में मेरी भूमिका नहीं'

जस्टिस वर्मा ने संसदीय समिति के सामने दाखिल किया जवाब

नई दिल्ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने सरकारी आवास पर मिले अधजले नोट के मामले में जांच कर रही संसदीय समिति के सामने अपना विस्तृत जवाब दाखिल किया है। अपने जवाब में उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ तौर पर इनकार किया है। मामले की जांच कर रही संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब में उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि इस मामले को लेकर उन पर महाभियोग क्यों चलाया जाना चाहिए। उनके अनुसार इस मामले में तो उनके आवास पर मौजूद पुलिस, अग्निशमन और सुरक्षा बल के अधिकारियों और कर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जिन्होंने मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।सूत्रों के अनुसार, जस्टिस वर्मा ने दावा किया है कि उनके आवासीय परिसर से कोई नकदी बरामद नहीं हुई। उन्होंने यह तर्क दिया कि अधिकारियों की ओर से घटनास्थल की सुरक्षा और जांच में हुई चूक का आरोप उन पर अनुचित तरीके से लगाया जा रहा है!

पासपोर्ट रैंकिंग

पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर

भारतीय पासपोर्ट मजबूत, 85 से 80वें नंबर पर आया

नई दिल्ली। भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले एक साल में बढ़ी है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 की रैंकिंग में भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 85 थी। नई रैंकिंग के मुताबिक, भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पासपोर्ट धारकों को बिना पूर्व वीजा कितने देशों में प्रवेश की अनुमति है, इसी आधार पर तय की जाती है। इधर पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। पाकिस्तान की नई रैंकिंग 98वीं है। पिछले साल 2025 में PAK की रेंकिंग 103 थी। वहीं, बांग्लादेशी पासपोर्ट 95 वें नंबर पर है और दुनिया का 8वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है।

सिंगापुरी पासपोर्ट लगातार दूसरे साल सबसे मजबूत

सिंगापुर लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना हुआ है, जिसे 227 में से 192 देशों में वीजा-फ्री एंट्री है। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, इन देशों के नागरिक 188 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। 2025 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर था और 57 देशों तक वीजा-फ्री पहुंच थी। 2024 में भी भारत की रैंक 80 थी। यानी 2025 में गिरावट के बाद 2026 में फिर से सुधार देखने को मिला है। हालांकि, वीजा-फ्री यात्रा में 2 देशों कम हो गए है।

पाकिस्तान का पांचवां सबसे कमजोर पासपोर्ट

पाकिस्तान ने भी रैंकिंग में 5 स्थान की छलांग लगाई है। पाकिस्तान की नई रैंकिंग 98वीं है। पिछले साल 2025 में PAK की रेंकिंग 103 थी। हालांकि, फिर भी उसका पासपोर्ट विश्व का पांचवां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। उसके नागरिक 31 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। पिछले साल पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट था। हालांकि, पाकिस्तानी नागरिक 33 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते थे।साल में दो बार यह रैंकिंग जारी की जाती है। पहली बार जनवरी और दूसरी बार जुलाई में इंडेक्स जारी किए जाते हैं। हेनली पासपोर्ट वीजा इंडेक्स की वेबसाइट के मुताबिक पूरे साल रियल टाइम डेटा अपडेट किया जाता है। वीजा पॉलिसी में बदलाव भी ध्यान में रखे जाते हैं। रैंकिंग इस आधार पर तय की जाती है कि किसी देश का पासपोर्ट होल्डर कितने दूसरे देशों में बिना पूर्व वीजा हासिल किए यात्रा कर सकता है।

DBD 8
दो बजे दोपहर
पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है
मुंबई
गुरुवार, 15 जनवरी 2026

आओ वोट करें

चुनावी कविता

वोट हमारा भले एक
पर है मजबूत हथौड़ा
जिस पर जितनी चोट पड़े
होते उतना चौड़ा

वोट उसे हम जाकर देंगे
होगा जो संवेदन
आन पड़े न्योछावर कर दे
अपना जो भी वेतन!

अब गर्म तवा हो गया कि
आओ चोट करें
चाहे जो भी हो
आओ वोट करें

राजेश पाठक

क्या बोलती पब्लिक

"चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों की परीक्षा है। लोग चाहते हैं कि नेता रोजगार, महंगाई, शिक्षा और सुरक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठोस काम करें, न कि सिर्फ चुनावी वादे करें।"

–रोहित पाटेकर, मुंबई

"मतदान हमारा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार है। सही उम्मीदवार का चयन करके ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और विकास की दिशा तय होगी। जागरूक होकर वोट देना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है।"

–सूरज महाले, मुंबई

हमें भेजें

अगर आप भी अपने विचार हमें भेजना चाहते हैं तो 8356804318 इस नंबर पर व्हाट्सप्प करें।

बीएमसी चुनाव में मामू फैक्टर

महिला, मुस्लिम और मराठी मानुस तय करेंगे मुंबई की सरकार

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

एशिया की सबसे अमीर नगरपालिकाओं में से एक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के लिए आज मतदान होने जा रहा है। लगभग तीन साल के लंबे इंतजार के बाद हो रहे इस चुनाव में 227 पार्षद सीटों के लिए 1,700 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुंबई की सड़कों, साफ-सफाई और बुनियादी ढांचे का भविष्य तय करने वाले इस महापर्व के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, ताकि 1 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

'मामू फैक्टर': राजनीति का नया समीकरण

इस चुनाव में सबसे चर्चित शब्द 'मामू फैक्टर' (MAMU) बनकर उभरा है, जो मराठी और मुस्लिम मतदाताओं के ध्रुवीकरण की रणनीति है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, मुंबई की आबादी में 28–34% मराठी और 18–20% मुस्लिम मतदाता हैं। यदि यह दोनों वर्ग एक साथ आते हैं, तो यह करीब 54% का एक शक्तिशाली वोट बैंक तैयार करता है, जो किसी भी दल की जीत और हार तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है।

ठाकरे भाइयों की एकजुटता और गठबंधन की चुनौती

बीएमसी चुनाव की एक और बड़ी विशेषता उद्धव ठाकरे (शिवसेना UBT) और राज ठाकरे (MNS) के बीच 20 वर्षों बाद हुआ गठबंधन है। यह गठबंधन न केवल मराठी वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश है, बल्कि भाजपा–शिंदे गठबंधन के 'हिंदुत्व' कार्ड के खिलाफ एक क्षेत्रीय पहचान और समावेशी राजनीति की चुनौती भी पेश कर रहा है। 'मराठी–मुस्लिम' की यह जुगलबंदी सीधे तौर पर सत्ताधारी गठबंधन के संसाधनों और रणनीति को टक्कर दे रही है।

मुस्लिम वोटों का गणित और रणनीतिक मतदान

मुस्लिम बहुल वार्डों में एआईएमआईएम (AIMIM) और विभिन्न एनसीपी गुटों की मौजूदगी के बावजूद, शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मतदाताओं को रणनीतिक मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका तर्क है कि ओवैसी या अन्य छोटे दलों को दिया गया वोट अंततः भाजपा को फायदा पहुँचाएगा। शिवसेना यूबीटी का दावा है कि अन्य दल चुनाव बाद भाजपा के साथ जा सकते हैं, इसलिए विपक्षी वोटों का एकमुश्त उनके पाले में आना जरूरी है।

महिला उम्मीदवारों का वर्चस्व और 50% आरक्षण

इस चुनाव का एक ऐतिहासिक पहलू यह है कि मैदान में पुरुषों (821) की तुलना में महिलाओं (879) की संख्या अधिक है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की नीति ने इसे संभव बनाया है। 227 में से 114 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने सामान्य सीटों पर भी महिला नेतृत्व पर भरोसा दिखाया है। भाजपा ने अपने 137 उम्मीदवारों में से 76 महिलाओं को टिकट देकर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को धार दी है।

बीएमसी वार्ड के जनसांख्यिकी आंकड़े

बीएमसी के 24 प्रशासनिक वार्ड (A से T तक) हैं। लेकिन चुनावों के लिए 227 वार्डों में बंटा हुआ है। कुल जनसंख्या लगभग 1.3 करोड़ से अधिक है, जिसमें शहर (आइलैंड) क्षेत्र में 32 लाख से अधिक, पश्चिमी उपनगरों में 57 लाख से अधिक और पूर्वी उपनगरों में 40 लाख से अधिक निवासी हैं। हर वार्ड में औसतन लगभग 54,000 निवासी हैं, जो जनसंख्या वृद्धि के अनुसार समायोजित किए गए हैं। कुल पंजीकृत मतदाता 1,03,44,315 हैं, जिसमें पुरुष 55 लाख से अधिक, महिलाएं 48 लाख से अधिक और अन्य श्रेणी के 1,099 मतदाता शामिल हैं। 227 वार्डों में 10,111 मतदान केंद्र हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों की जनसंख्या 45,000 से 63,000 के बीच है, जिसमें एससी (अनुसूचित जाति) और एसटी (अनुसूचित जनजाति) की संख्या क्रमशः 400–10,000 और 100–2,700 के बीच है। आरक्षण में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए सीटें शामिल हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 114 वार्ड आरक्षित हैं।

बीएमसी के मुस्लिम बहुल वार्ड

धार्मिक जनसांख्यिकी में मुंबई विविध है, जहां हिंदू बहुमत में हैं (65.99% से अधिक), उसके बाद मुस्लिम (20.65%), बौद्ध (4.85%), जैन (4.10%), ईसाई (3.27%) और अन्य हैं। आइलैंड सिटी में मुस्लिमों का हिस्सा अधिक (25.06%) है, जबकि उपनगरों में 19.19% है। मुस्लिम–प्रभावित या बहुल वार्ड लगभग 31 हैं, और महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले अन्य 29 वार्ड हैं, कुल मिलाकर लगभग 50–60 वार्डों में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रमुख क्षेत्रों में नागपाड़ा, बायकला, मझगांव, माहिम, गोवंडी, चीता कैंप, कुरला, जोगेश्वरी, मिल्लत नगर आदि शामिल हैं। 2026 चुनावों में 330 मुस्लिम उम्मीदवार (कुल उम्मीदवारों का 19%) मैदान में हैं, जिनमें से लगभग 80% मुस्लिम–प्रभावित वार्डों से हैं।

भाषाई विविधता

भाषाई और जातीय जनसांख्यिकी में महाराष्ट्रियन (मराठी भाषी) 30–35% (कुछ अनुमानों में 32–42%) हैं, गुजराती 14–20%, हिंदी (उत्तर भारतीय) 20%, दक्षिण भारतीय भाषाओं वाले 10% और अन्य हैं। मराठी मतदाता 130 वार्डों में 35% से अधिक हैं (कुछ में 70% तक), जबकि गैर–मराठी (हिंदी/गुजराती) लगभग 60 वार्डों में प्रभावी हैं। 'मामू फैक्टर' (मराठी–मुस्लिम वोट) ठाकरे गठबंधन के लिए 90+ वार्डों में फायदेमंद हो सकता है, खासकर जहां मराठी बहुमत और मुस्लिम समर्थन मिलता है। इसके साथ ही यह तय होगा कि मुंबई के इस 'सत्ता के सिंहासन' पर किसका कब्जा होगा।

महायुति और एमवीए का सर्वाइवल टेस्ट

बीएमसी का परिणाम तय करेगा महाराष्ट्र का भविष्य

डीबीडी संवाददाता | मुंबई

74,000 करोड़ रुपये से अधिक के बजट वाली देश की सबसे अमीर और प्रभावशाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावों ने महाराष्ट्र की राजनीति में अभूतपूर्व उथल-पुथल मचा दी है। इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है और ऐसे अजीबोगरीब गठबंधन सामने आए हैं, जिन पर यकीन करना मुश्किल है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर दल ने अपनी सुविधा अनुसार पाले बदल लिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएमसी चुनाव के नतीजे न केवल मुंबई की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी यह तय करेंगे, बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य की राजनीतिक दिशा भी निर्धारित करेंगे।

'मराठी अस्मिता' या राष्ट्रीय राजनीति का वर्चस्व

इन चुनावों में 'मराठी अस्मिता' सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा बनकर उभरी है। 20 साल बाद एक मंच पर आए उद्धव ठाकरे (यूबीटी) और राज ठाकरे (मनसे) ने इसे 'मुंबई की आखिरी जंग' करार दिया है। ठाकरे बंधुओं ने भाजपा पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश रचने और हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या 30–35% मराठी वोट बैंक और विकास के मुद्दों (पॉटहोल, प्रदूषण) पर केंद्रित 'जेन–जेड' (युवा) वोटरों के बीच संतुलन बन पाएगा। वहीं, राज ठाकरे के आक्रामक तेवरों से उत्तर भारतीय और गुजराती वोटरों के बिदकने का खतरा भी गठबंधन पर मंडरा रहा है। अगर ठाकरे गठबंधन मजबूत प्रदर्शन करता है, तो अस्मिता राज्य स्तर पर वापस आएगी। अन्यथा, राष्ट्रीय राजनीति का वर्चस्व बढ़ेगा।

महायुति कितनी एकजुट?

महायुति में दरार : अजित पवार की अलग राह राज्य की सत्ताधारी महायुति (भाजपा–शिंदे सेना–अजित एनसीपी) में बीएमसी चुनावों को लेकर एकराय नहीं दिख रही है। भाजपा (137 सीट) और शिंदे सेना (90 सीट) मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अजित पवार की एनसीपी ने 94 सीटों पर अलग उम्मीदवार उतारकर गठबंधन में दरार डाल दी है। कई वार्डों में होने वाली यह 'फ्रेंडली फाइट' अंततः महायुति के वोटों के बंटवारे का कारण बन सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि इस चुनाव में भाजपा एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन करती है और शिंदे सेना कमजोर साबित होती है, तो राज्य में गठबंधन धर्म की जगह एकल दलीय वर्चस्व की राजनीति जोर पकड़ सकती है।

एमवीए के लिए सर्वाइवल टेस्ट

महा विकास अघाड़ी (एमवीए—कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी, एनसीपी एसपी) का बीएमसी चुनावों में स्ट्रक्चर पूरी तरह खत्म हो चुका है, जो इसके भविष्य पर सवाल उठाता है। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए) के साथ मिलकर 143 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि उद्धव ठाकरे ने अपने पुराने साथियों को छोड़कर मनसे के साथ हाथ मिला लिया है। 2024 के विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद, एमवीए का यह बिखराव गठबंधन के 'साइलेंट अंत' की ओर इशारा कर रहा है। अगर ठाकरे गठबंधन मजबूत होता है, तो क्षेत्रीय अस्मिता वाली नई विपक्षी एकता बनेगी। कांग्रेस की कमजोरी (2024 में 16 सीटें) और डिफेक्शन से पार्टी हाशिए पर जा सकती है। एमवीए की हार से इसका अंत तय होगा और विपक्षी एकता और मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस–VBA अच्छा प्रदर्शन करती है, तो सेकुलर–दलित–माइनॉरिटी आधार पर नई शुरुआत हो सकती है। कुल मिलाकर, बीएमसी चुनाव महायुति और एमवीए के लिए सर्वाइवल टेस्ट है।